A Daily News Magazine

इंदौर

मंगलवार, 10 फरवरी, 2026

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 130, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

ब्राह्मण हैं या जमींदार : आखिर क्या हैं बिहार के भूमिहार?

कृष्ण मुरारी

बिहार के एक जिले बेगूसराय में एक नया आंदोलन शुरू हुआ है। इसे कभी 'बिहार का लेनिनग्राद' कहा जाता था और जो अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का गढ़ बन चुकी है। यह लड़ाई किसी विचारधारा की नहीं है, बल्कि बिहार की एक बड़ी जाति भूमिहारों की पहचान की है। वे साल 2015 में हुई एक गलती को ठीक करना चाहते हैं और करीब 95 साल पहले ब्रिटिश राज के दौरान मिली अपनी 'भूमिहार-ब्राह्मण' पहचान वापस चाहते हैं। इसे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का उल्टा रूप भी कहा जा सकता है।

इस भूमिहार आंदोलन के बीच एक बड़ा सवाल है: आखिर हम हैं कौन? बेगूसराय के बिहट गांव में, जिसे वामपंथी जोश के कारण 'मिनी मॉस्को' कहा जाता है, एक अनौपचारिक गांव की चौपाल में 26 साल के विक्रम सिंह ने समुदाय का नारा बुलंद किया – ब्राह्मण जाति बहाल करो। यह नारा अब पूरे बिहार में भूमिहारों के बीच गूंज रहा है। वे 1931 की जाति जनगणना में इस्तेमाल किए गए नाम पर वापस जाना चाहते हैं, जिसमें उन्हें 'भूमिहार ब्राह्मण' के रूप में दर्ज किया गया था। इससे उनकी पहचान ऐसे ब्राह्मणों के रूप में बनी थी जो खेती और ज़मींदारी करते थे, लेकिन पिछले एक दशक में, बिहार सवर्ण आयोग ने अपनी 2015 की रिपोर्ट में सिर्फ 'भूमिहार' शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सरकारी कागज़ों में वही नाम चलन में आ गया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समय हुए जाति सर्वे और भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने की बड़ी योजना ने भूमिहारों के बीच चिंता बढ़ा दी है। यह समुदाय आने वाली राष्ट्रीय जाति जनगणना से पहले अपने आधिकारिक नाम को लेकर फैसला चाहता है। यह जनगणना ब्रिटिश शासन के लगभग सौ साल बाद पहली बार होने जा रही है। उन्हें डर है कि अगर 'भूमिहार-ब्राह्मण' की प्रतिष्ठित पहचान चली गई, तो उनकी ऊंची जाति की स्थिति हमेशा के लिए प्रभावित हो सकती है।

बरौनी-बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र के धुएं से भरे बिहट में सिंह ने कहा, 'अब भूमिहारों की पहचान कोई और तय नहीं करेगा। यह हमारे लिए फैसला करने का समय है। हमारे पूर्वज योद्धा, विद्वान और किसान थे। अगर हमने यह मौका गंवा दिया, तो भूमिहार ब्राह्मण समुदाय की पहचान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।'

जाति सर्वे के बाद अपनी ऐतिहासिक पहचान मिटने का डर बढ़ गया है। सरकार से मांग की जा रही है कि आधिकारिक रिकॉर्ड और जाति प्रमाण पत्रों में फिर से 'बाभन' (भूमिहार ब्राह्मण) शब्द जोड़ा जाए। पटना में सवर्ण आयोग के दफ्तर की मेज़ों पर याचिकाओं के ढेर लगे हैं। कई याचिकाएं दो बातों पर टिकी हैं- ब्रिटिश दौर की जाति जनगणना के रिकॉर्ड और योद्धा ऋषि परशुराम से जुड़ी वंशावली। भूमिहारों की पहचान हमेशा उलझन में रही है। अंग्रेज़ों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूमिहारों को ब्राह्मण का दर्जा दिया था, लेकिन बिहार में उन्हें 1800 के दशक के आखिर तक वैश्य वर्ग में रखा गया। बाद में, जब उन्होंने संगठित होकर दबाव बनाया तब औपनिवेशिक शासकों ने उन्हें ब्राह्मण का टैग दिया। अखिल भारतीय भगवान परशुराम परिषद की ओर से सवर्ण आयोग को लिखे पत्र में सरकार से आधिकारिक रिकॉर्ड में 'भूमिहार ब्राह्मण' का पूरा जाति नाम बहाल करने की मांग की गई है। 19वीं सदी के औपनिवेशिक सर्वे करने वालों ने भूमिहारों को अलग-अलग तरह से बताया। फ्रांसिस बुकानन-हैमिल्टन ने उन्हें 'सैन्य ब्राह्मण' कहा। बाद के समाजशास्त्रियों और नृवंशविज्ञान अध्ययनों में उन्हें ज़मीन रखने वाला खेती करने वाला उच्च वर्ग और ऐसे ब्राह्मण बताया गया जो भिक्षा नहीं मांगते थे। जाति सर्वे के मुताबिक, इस समय वे बिहार की कुल आबादी का 2.87 प्रतिशत हैं।

जब बिहार सरकार ने अक्टूबर 2023 में अपनी जाति सर्वे रिपोर्ट जारी की, तो पटना के एक टीवी पत्रकार धीरेंद्र कुमार नाराज़ हो गए। कुछ ही हफ्तों में कुमार ने नाम बदलकर 'भूमिहार ब्राह्मण' कराने के लिए पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी।

सामाजिक सम्मान के अलावा, संपत्ति भी भूमिहारों की एक बड़ी चिंता है। बिहार जैसे राज्य में, जहां 60 प्रतिशत से ज़्यादा अपराध ज़मीन और संपत्ति विवाद से जुड़े हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने की बड़ी योजना में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर में सिर्फ 'भूमिहार' टैग है। इससे भविष्य में ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद होने की आशंका बढ़ गई है।

अप्रैल 2025 में मोदी सरकार ने 2027 की जनगणना में जाति की गिनती कराने की घोषणा कर दी। कुमार ने कहा, 'अगर केंद्र सरकार भी जनगणना में हमारी जाति के लिए 'भूमिहार' शब्द ही इस्तेमाल करती है, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। पहले हमने गृहमंत्रालय से संपर्क किया।' गृह मंत्रालय ने जवाब के लिए इसे राज्य सरकार के पास भेज दिया। बिहार सरकार ने पिछले साल इस मुद्दे पर सिफारिशें देने के लिए मामला सवर्ण आयोग को भेजा था। सवर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह, जो खुद भूमिहार समुदाय से हैं। आयोग के अध्यक्ष नवंबर में मुज़फ्फरपुर गए, तो अखिल भारतीय भगवान परशुराम परिषद- जो एक भूमिहार संगठन है, के प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें एक 'वर्तमान सरकारी रिकॉर्ड में अधूरे जाति नाम भूमिहार के स्थान पर पूरा नाम भूमिहार ब्राह्मण शामिल करने के संबंध में' ज्ञापन सौंपा। बिहार की जटिल सामाजिक स्थिति में भूमिहार समुदाय अपनी पहचान को लेकर दोहरी उलझन में है। समुदाय के कुछ लोग अपनी ब्राह्मण जड़ों पर ज़ोर देना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग ओबीसी का दर्जा मांग रहे हैं। ज़मीन के लगातार बंटवारे के बावजूद, बिहार में भूमिहारों को अब भी जमींदारी ताकत से जोड़ा जाता है। अनुमान है कि बिहार की 39 प्रतिशत ज़मीन भूमिहारों के कब्ज़े में है। राज्य में भू सुधार पर बंद्योपाध्याय आयोग ने 2008 में एक रिपोर्ट दी थी, लेकिन नीतीश कुमार सरकार ने उसे कभी सार्वजनिक नहीं किया। 2023 की जाति सर्वे रिपोर्ट ने इन धारणाओं को सीधी चुनौती दी। रिपोर्ट के मुताबिक, 27.58 प्रतिशत भूमिहार 'गरीब' श्रेणी में आते हैं, यानी उनकी मासिक आय 6 हजार रुपये से कम है। आर्थिक रूप से उनसे ज़्यादा कमजोर सिर्फ अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ही हैं।

इन्हीं नतीजों के आधार पर पटना के भूमिहार कार्यकर्ता आलोक कुमार सिंह ने जनवरी 2024 में एक बैठक बुलाई और 'भूमिहार ओबीसी संघर्ष मोर्चा' की घोषणा की। यह संगठन भूमिहारों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर अभियान चला रहा है। भूमिहार अभियान से जमींदारों और अभिजात वर्ग द्वारा बनाए गए दो बड़े संगठन सामने आए. पहला था प्रधान भूमिहार ब्राह्मण सभा, जिसकी स्थापना 1889 में हुई। इसके बाद 1896 में भूमिहार ब्राह्मण महासभा बनाई गई।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

भारत-सेशेल्स के बीच एमओयू पर हो गए हस्ताक्षर

● मोदी बोले-हम साथ मिलकर हिंद महासागर के भविष्य को आकार देंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी की मौजूदगी में हैदराबाद हाउस में भारत और सेशेल्स के बीच स्ब्श पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, सेशेल्स के राष्ट्रपति चुने जाने पर मैं राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है, उनकी यह यात्रा ऐसे शुभ वर्ष में हो रही है जब सेशेल्स का 50वां स्वतंत्रता दिवस और हमारे राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मुझे विश्वास है कि यह हमें निरंतर नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा, एक मैरिटाइम पड़ोसी और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशेल्स भारत के महासागर विजन का अभिन्न अंग है। हमारा सहयोग

जल, थल और नभ को समाहित करता है। आज की चर्चाओं में हमने इस साझेदारी को और सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। अपने आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखने पर हम सहमत है। लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाने के साथ-साथ हम फिनटेक और डिजिटल सॉल्यूशन में भी आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा, हमारे सभी प्रयास सेशेल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम 175 मिलियन डॉलर के स्पेशल पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ई-मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, रक्षा और मैरिटाइम सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं का समर्थन देंगे, मुझे खुशी है कि सेशेल्स के सिविल सेवकों की भारत में ट्रेनिंग के लिए आज एमओयू किया जा रहा है, तकनीकी क्षेत्र में करीबी सहयोग से हम अपने सहयोग को एक भविष्यवादी दिशा दे रहे हैं।

ब्लू इकोनॉमी हमारे लिए एक स्वाभाविक सहयोग का क्षेत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समुद्री पड़ोसी के रूप में ब्लू इकोनॉमी हमारे लिए एक स्वाभाविक सहयोग का क्षेत्र है। समुद्री अनुसंधान, क्षमता निर्माण, डेटा साझाकरण जैसे क्षेत्रों में हम भारत की विशेज्ञता सेशेल्स के साथ साझा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा, साथ मिलकर हम न सिर्फ द्विपक्षीय सहयोग को, बल्कि हिंद महासागर के लिए एक साझा भविष्य को भी आकार देंगे। भारत–सेशेल्स संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति हमारे लोगों से लोगों के संबंध हैं। सेशेल्स में बसे भारतीय समुदाय ने सेशेल्स के सामाजिक और आर्थिक जीवन में उल्लेखनीय योगदान दिया है और हमारी मित्रता को मजबूत भी किया है। आज हमने पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और खेल के माध्यम से इन संबंधों को और सशक्त करने पर विचार–विमर्श किया।

शरद की सुबह

कलेजे वाले कब के चले
गए इंसाफ लेकर
मुर्दे अब भी कतार में
खड़े हैं फरियाद लेकर
हम तो चल ही दिए थे
अपना हिसाब देकर के
बारिशें फिर लौट
आईं तेरी याद लेकर
कोई दर ले गया तो
कोई दीवार ले गया
और इक हम थे के बैठे
रहे बुनियाद लेकर
शर्मिंदा हैं आज
जंगल के सब रहनुमा
परिंदा पहुंचा है खुद
अपना सैय्याद लेकर
अब तो हम यहीं रह
जाएंगे कुछ ले देकर
और जाएंगे भी कहां
दिल ए बरबाद लेकर।

– शैलेन्द्र सिंह

बजट सत्र के 9वें दिन भी लोकसभा में हुआ हंगामा

● ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में विपक्ष

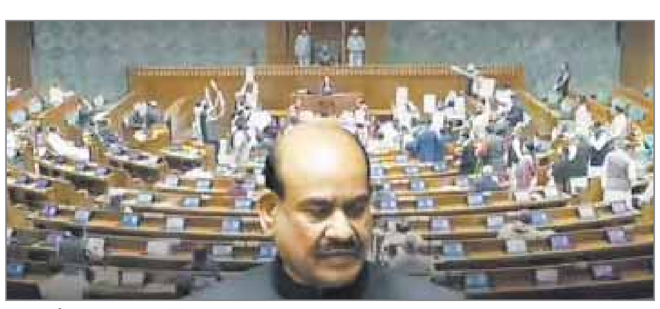

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के बजट सत्र के दौरान लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। सोमवार को भी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया और इसकी कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नियम से बोलने का हक सभी को है। सदन गतिरोध और नारेबाजी करने के लिए नहीं है। वहीं, यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकता है। विपक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगाए और हंगामा किया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं की सदन में बैठक हुई, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी को अगर सदन में बोलने दिया जाएगा तो सदन चलेगा नहीं तो संसद में हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद पहुंचे। इस दौरान एक सवाल के जवाब में मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कौन कहता है कि आज सदन नहीं चलेगा।

पहली बार बालाघाट में होगी कैबिनेट, सीएम का ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने नक्सली समस्या को 'कैंसर' बताया

बालाघाट। नक्सल समाप्त होने के बाद पहली बार मोहन कैबिनेट की बैठक बालाघाट में होगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इसकी घोषणा की है। सोमवार को सीएम बालाघाट पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नक्सली गतिविधि पर लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम ने हॉक फोर्स के 60 जवानों को बैच लगाकर आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन दिया। जिन्होंने नक्सली मुठभेड़ में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। सीएम जिले में 100 करोड़ 90 लाख रुपए के 27 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। यह पदोन्नति उन जवानों को दी गई, जिन्होंने 14 जून 2025 को रूपझर थाना क्षेत्र के पचामादादर-कटेझिरिया पहाड़ी जंगल में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीएम ने पुलिस की विधांजलि कार्यक्रम, एकल केंद्र और 32 थानों के आईएसओ मिलने की शॉर्ट वीडियो फिल्म का शुभारंभ किया। बालाघाट में सीएम यादव ने नक्सली समस्या को 'कैंसर' बताया। वहीं उन्होंने तात्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री लिखीराम की नक्सलियों की ओर से हत्या किए जाने पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि आज कांग्रेसी खामोश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री की हत्या का बदला उनकी सरकार ने लिया। इस दौरान सीएम ने पीएम मोदी का तीन बार नाम लिया। क्रमपूर्व पदोन्नति में शामिल जवानों को मुख्यमंत्री ने फीता काटकर सम्मानित किया।

दिया बड़ा गिफ्ट

60 जवानों को आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन प्रदान किया

60 हॉकफोर्स जवानों को क्रमपूर्व पदोन्नति के साथ ही 10 परिवारों के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाएगी। यह वे 14 परिवार हैं जिन्होंने अपने परिजनों को नक्सली घटना में खोया है। जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के साथ हो नक्सली घटना में शहीद होने वाले आमजन के परिवार के 14 परिवारों को नौकरी का पत्र सौंपा। साथ ही बैगा महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आदिवासी टीमों और नक्सल में बेहतर काम करने वाले सीआरपीएफ को भी सीएम ने सम्मानित किया। इस अभियान में हॉक फोर्स के जवानों ने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के मलाजखंड दलम के पांच सदस्यों रीता उर्फ तुब्बी, श्रीरांगु हिड़ामी उर्फ देवचंद, सुमन, ईमला उर्फ तुलसी और रवि मड़ावी उर्फ बदरे को मार गिराया था। सीएम डॉ. यादव पुलिस लाइन में आयोजित 'साहसिक अभियान' कार्यक्रम में इन जवानों को सम्मानित करते हुए उन्हें क्रम से पूर्व पदोन्नति प्रदान करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

● फरीदाबाद जेल में आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या

राम मंदिर उड़ाने की साजिश रची थी हमलावर और अब्दुल एक ही बैरक में थे

फरीदाबाद (एजेंसी)। हरियाणा की फरीदाबाद जेल में बंद आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई है। रविवार देर रात जेल में मर्डर केस में बंद अरुण चौधरी उर्फ अब्बू जट नाम के कैदी ने उस पर नुकीली चीज से हमला किया। दोनों को हाई सिक्योरिटी वाली बैरक में एक साथ बंद किया गया था। कत्ल का पता चलते ही जेल अधिकारी बैरक में पहुंचे। इसके बाद आतंकी की लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया गया। 20 साल के आतंकी अब्दुल को गुजरात एटीएस ने मार्च 2025 में पकड़ा था। जांच में पता चला कि वह अलकायदा इन इंडियन सब-कांटिनेंट के कुख्यात आतंकी अबू सूफियान के संपर्क में था। उसने अयोध्या में राम मंदिर उड़ाने की साजिश रची थी। वहीं कत्ल करने वाला कैदी अरुण चौधरी का नाम भी चर्चित अक्षय शर्मा हत्याकांड में आया था।

भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी का भारत ने लिया बदला

● ईरान के 3 तेल टैंकर को जब्त कर दे दिया करारा जवाब

तेहरान/नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और ईरान के बीच दशकों से काफी मजबूत सबंध रहे हैं। लेकिन पिछले एक महीने में कुछ दिलचस्प घटनाएं घटी हैं। जनवरी 2026 में पता चला था कि ईरान ने भारत के 16 नाविकों को गिरफ्तार कर लिया है।

बाद में पता चला कि पिछले साल 8 दिसंबर को एक टैंकर वैलेंट रोर को ईरान ने पीछा किया था और फिर उससे 16 भारतीय नाविकों को पकड़ लिया था। इस जहाज के कैप्टन विनोद परमार ने अपने भाई को टेलीफोन पर 8 दिसंबर को बताया था कि 18 क्रू मेंबर्स वाले उनके जहाज का तेजी से पीछा कर रही है।

इसके बाद लाइन कट गई थी। भारतीय नाविकों के परिवार वालों ने बताया कि इसके बाद ईरानी नौसेना ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की, टैंकर को जब्त कर लिया

और 10 क्रू मेंबर्स गायब हो गए। ये जहाज दुबई की कंपनी ग्लोरी इंटरनेशनल टैंकर था, जिसका नाम वैलेंट रोर है और ये डिब्बा पोर्ट के पास इंटरनेशनल पानी में चल रहा था, जब इसका पीछा कर इसे पकड़ा था। भारतीयों के अलावा और लोग भी थे। ईरान के इस जहाज में भारतीय कोस्टगार्ड के कई लोग भी शामिल थे।

भारतीय नाविकों वाले जहाज पर की थी गोलीबारी

गिरफ्तार किए गये नाविकों के परिवार वालों के हवाले से इंडिया टुडे ने 16 जनवरी के एक रिपोर्ट में कैप्टन परमार के हवाले से बताया था कि जब यह जहाज आगे टेक्निकल मदद के लिए खोर फक्कन की ओर जा रहा था तो कैप्टन ने देखा कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, जो ईरान की आर्म्ड फोर्सेज की सबसे ताकतवर यूनिट है, उनका पीछा कर रहे हैं। यह सब तब हुआ जब टैंकर इंटरनेशनल पानी में था। उस जहाज के चीफ ऑफीसर अनिल कुमार सिंह की की पत्नी गायत्री ने इंडिया टुडे से कहा कि जब 8 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे उन्होंने घबराकर फोन किया, तो उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। यानि एजेंसी ने भारतीय क्रू मेंबर्स पर गोलियां भी चलाई।

सुबह सवेरे

इंदौर ■ मंगलवार, 10 फरवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

हेल्थकेयर के क्षेत्र में भारत की बड़ी उपलब्धि

- एम्स दिल्ली बना दुनिया का छठा सर्वश्रेष्ठ अस्पताल
- महाराष्ट्र का टाटा मेमोरियल मुंबई 13वें स्थान पर रहा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के हेल्थकेयर सेक्टर के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली को ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल टॉप 250 हॉस्पिटल रैंकिंग 2026 में दुनिया का छठा सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है। इस उपलब्धि के साथ एम्स ने अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन, ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स और मायो क्लिनिक जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच अपनी सशक्त पहचान दर्ज कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक, एम्स को केयर परसेप्शन, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड स्ट्रेंथ और वैश्विक प्रतिष्ठा जैसे पैमानों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के

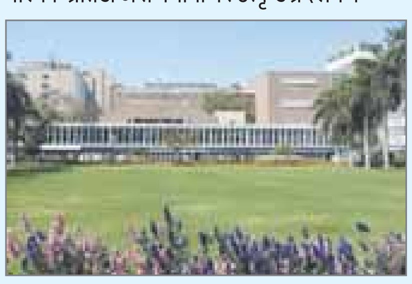

आधार पर यह स्थान मिला है। खास बात यह रही कि एम्स का केयर स्कोर टॉप रैंक वाले अस्पताल से महज 1.1 अंक कम रहा, जो सीमित संसाधनों के बावजूद इसकी गुणवत्ता और भरोसे को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक सरकारी संस्थान का दुनिया के टॉप 10 में शामिल होना भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की वैश्विक साख को नई ऊंचाई देता है। एम्स दिल्ली देश का प्रमुख तृतीयक स्वास्थ्य संस्थान है, जहां हर साल लाखों मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। यहां अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं, सुपर स्पेशियलिटी ट्रेनिंग और सैकड़ों शोध परियोजनाएं संचालित होती हैं।

चंद्रयान-4 को लेकर इसरो को मिली बड़ी सफलता

- बहुत जल्द धरती पर वापस लौटेगा भारत का यह मिशन

नई दिल्ली (एजेंसी)। चंद्रयान-4 मिशन को लेकर इसरो को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसरो के स्पेस ऐप्लिकेशन सेंटर ने अब तक के सबसे कठिन मून मिशन के लिए लैंडिंग की जगह खोज ली है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लगभग 1 वर्ग किलोमीटर का पैच है जहां चंद्रयान-4 की सफल लैंडिंग करवाई जा सकती है। बता दें कि यह इसरो का पहला रिटर्न मिशन होगा। यानी चंद्रयान-4 को वापस धरती पर भी लाना है। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से भजी गई हाई रिजोल्यूशन

तस्वीरों से इस जगह को खोजा है जहां चंद्रयान-4 को उतारा जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह पूरा अध्ययन अमिताभ के सुरेश, अजय के पाराशर, कनन वी अय्यर, अब्दुल एस, श्वेता वर्मा त्रिवेदी और नितांत दुबे ने की है। इस मिशन में प्रोपल्सन मॉड्यूल के अलावा डिसेंटर और असेंडर मॉड्यूल भी होंगे। इसके अलावा ट्रांसफर मॉड्यूल और रीएंट्री मॉड्यूल भी काम करेगा। यह मिशन भारत के लिए बहुत खास होने वाला है। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर लैंडिंग करके मिट्टी और पत्थरों के सैंपल इकट्ठे करना था।

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सभी कार्यकर्ता अपना अमूल्य योगदान दें : अजय जामवाल

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल ने सोमवार को सीहोर जिला कार्यालय में कामकाजी बैठक, जनप्रतिनिधियों की बैठक और जिला कोर ग्रुप की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए कार्य रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र अैर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। भाजपा की डबल इंजन सरकार हर समाज वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्ष 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को

विकसित बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। कामकाजी बैठक को संभाग प्रभारी डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान एवं जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा ने भी संबोधित किया। इस दौरान मंच पर प्रदेश शासन के मंत्री श्री करणसिंह वर्मा, विधायक श्री रमाकांत भार्गव, जिला प्रभारी विकास विरानी, विधायक श्री सुदेश राय एवं गोपाल इंजीनियर उपस्थित रहे। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल ने कहा कि जिले के सभी पार्टी पदाधिकरी मंडल और शक्ति केंद्रों तक प्रवास करें और कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को और मजबूत करने के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और समाज के हर वर्ग के लोगों कल्याण, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। आप सभी पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर तक संपर्क कर भाजपा की डबल इंजन सरकार की हितग्राही मूलक और जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं और पात्र हितग्रहियों को उनका लाभ दिलाने के लिए कार्य करें।

कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका

उन्नाव रेप केस में जमानत देने से कर दिया इनकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए और सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। टॉप कोर्ट ने सेंगर को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए पूर्व बीजेपी एसएलए के खिलाफ मामले को फास्ट ट्रैक करने का निर्देश भी दिया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को तीन महीने में अपील पर फैसला करने को कहा है। गौरतलब है कि सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट मे जमानत याचिका दाखिल की थी। सेंगर की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि उसे 10 साल की सजा हुई थी।+

तय समय में ही खत्म होगा नक्सलवाद

- शाह ने कहा-बस्तर की पहचान बारूद नहीं, संस्कृति है

बस्तर पंडुम में कहा-यह सबसे विकसित संभाग बनेगा

जगदलपुर (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर की पहचान बारूद से नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध संस्कृति से है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद का तेजी से सफाया हो रहा है और सरेंडर करने वाले नक्सलियों को कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन स्कूल और अस्पताल जलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तय समय में नक्सलवाद खत्म होगा। शाह ने भरोसा दिलाया कि बस्तर को प्रदेश का सबसे विकसित संभाग बनाया जाएगा। उन्होंने ये बातें जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित बस्तर पंडुम के मंच से कही। इससे पहले स्वागत के दौरान उन्हें कौड़ी की माला और पारंपरिक पगड़ी पहनाई गई। जगलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित बस्तर पंडुम का समापन हो गया है। मंच से शाह ने चेतावनी दी है कि नक्सली हथियार डाले,नहीं उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा।

- **जवानों के साहस-संकल्प से बदल रही बस्तर की तस्वीर-** छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में 45 वर्षों से अधिक समय तक नक्सलवाद का प्रभाव रहा। बस्तर का क्षेत्रफल केरल राज्य से भी बड़ा है। लाल आतंकवाद के कारण यहां के लोगों को लंबे समय तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाईं। लेकिन गृह मंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति और ठोस रणनीति के चलते मात्र दो वर्षों में यहां शांति स्थापित हुई है। गृह मंत्री का हमारे बीच होना बस्तर के लिए ऐतिहासिक क्षण है। बस्तर पंडुम, बस्तर की संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। एक समय था जब यह विश्वास करना कठिन था कि बस्तर से नक्सलवाद कभी समाप्त होगा।

- सी-20 देशों में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ सबसे तेज

अनुमान-अगले वित्त वर्ष भारत की जीडीपी 6.4 फीसदी की दर से बढ़ेगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने सोमवार को भारतीय इकोनॉमी को लेकर नए अनुमान जारी किए हैं। मूडीज के मुताबिक, अगले वित्त वर्ष (2026-27) में भारत की जीडीपी 6.4 फीसदी की दर से बढ़ सकती है। मूडीज ने कहा कि यह रफ्तार दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले सी 20 देशों के ग्रुप में सबसे ज्यादा होगी। एजेंसी ने इसके पीछे मजबूत घरेलू खपत, सरकार के नीतिगत फैसलों और देश के स्थिर बैंकिंग सिस्टम को मुख्य वजह बताया। मूडीज का यह अनुमान भारत सरकार और रिजर्व बैंक के अनुमान के मुकाबले थोड़ा कम है। पिछले महीने संसद में पेश हुए इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2027 के लिए 6.8 से 7.4 फीसदी की ग्रोथ का अनुमान बताया गया था। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही के लिए करीब 7 फीसदी ग्रोथ की उम्मीद जताई है। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2025 में जीएसटी के नियमों में हुए बदलाव और पर्सनल इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाए जाने से लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। रेटिंग एजेंसी ने अपनी बैंकिंग सिस्टम आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय बैंकों की हालत बेहतर बनी रहेगी। रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के बाद एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़ी कंपनियों की स्थिति में सुधार आएगा।

2046 तक देश में बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग होंगे

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान के सभी 31 वृद्धाश्रमों (ओल्ड एज होम) की जांच होगी। वहां रहने वाले बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधाओं की हकीकत सामने आएगी। बुजुर्गों को मेडिकल की सुविधा मिल रही है कि नहीं, खाने की क्वालिटी, बिल्डिंग की स्थिति, साफ-सफाई से लेकर सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, इन सब बिंदुओं पर हाईकोर्ट ने 15 फरवरी तक रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने नाराजगी जताई राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने यह जिम्मेदारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को दी है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि 2046 तक देश में बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग होंगे।

बारामती प्लेन क्रैश के बाद ऐक्शन में सरकार

- 400 से ज्यादा हवाई पट्टियों की जांच हुई शुरू

बारामती (एजेंसी)। बारामती प्लेन क्रैश के बाद सरकार ने देशभर की 400 से ज्यादा अनियंत्रित हवाई पट्टियों को लेकर जांच शुरू की है। सरकार का प्लान है कि इन हवाई पट्टियों को लेकर एकीकृत नियम बनाए जाएं और इसकी देखरेख डीजीसीए और राज्य सरकार के तहत हो। जांच में पता लगाया जाएगा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर, संचार सुविधा और अग्निशमन को लेकर कितनी तैयारी है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन के साथ हवाई पट्टी का प्रबंधन करने वाले किस तरह संपर्क साधते हैं। 28 जनवरी को बारामती में एक प्लेन क्रैश हो गया था जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई थी। डीजीसीए ने इसके बाद एयरपोर्ट्स पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में सुधार की कवायद शुरू कर दी है।

वहीं इस तरह की हवाई पट्टियों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भी सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है। ये हवाई पट्टियां या तो राज्य सरकारों के अंडर में हैं या फिर फ्लाइट ट्रेनिंग संगठनों और प्राइवेट संचालकों की हैं।

हो जाइए तैयार ! एक बार फिर लौटेगी कंपकंपाने वाली ठंड

कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश का अलर्ट,कोहरे की भी चेतावनी

नई दिल्ली (एजेंसी)।। देशभर में एक बार फिर मौसम करवट बदलने की तैयारी में है। फरवरी की शुरुआत में जहां ठंड में हल्की सी राहत मिली थी, वहीं अब एक बार फिर कंपकंपाने वाली हवाओं के चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी 10 फरवरी से कई राज्यों में मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुबातिक, आज पूर्वी यूपी और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में शीतलहर भी चलेगी। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होगी।

- **उत्तर-पश्चिम भारत का तापमान-** अगर बात करें तापमान की तो तापमान में कोई खास उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। अगले 2 दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे लगभग 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, उसके बाद के 2 दिनों में धीरे-धीरे लगभग 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है और उसके बाद के 3 दिनों में बदलाव नहीं होगा।

बिहार बजट सत्र में दरभंगा रेप-मर्डर कांड पर बवाल

- राबड़ी देवी के नेतृत्व में महिला विधायकों ने किया प्रदर्शन

पटना (एजेंसी)। बिहार के दरभंगा में एक छह साल की बच्ची के साथ हैवानियत की वारदात पर विधानमंडल के बजट सत्र में हंगामा हुआ। विधानसभा के पोर्टिको में विपक्षी सदस्यों ने पोस्टर लहराए तो विधान परिषद में सीएम नीतिश कुमार और नेता विरोधि दल राबड़ी देवी आमने-सामने आ गए। शोर शराब बढ़ता देख सदन की कार्यवाही को दोपहर ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। रबड़ी देवी के नेतृत्व में महिला विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन भी किया। दरभंगा में शनिवार की रात एक छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गयी। रविवार को बिहार भारी हंगामा, पत्थरबाजी और लाठीचार्ज का गवाह बना। महिला विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य में बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है।

विदेशी धरती पर करनाल के युवक की आखिरी विदाई

- 7 महीने पहले एक्सीडेंट में मौत,डीएनए से हुई पहचान
- मिलान के बाद मिली बॉडी

करनाल (एजेंसी)। नियति का क्रूर खेल देखिए कि जिस बेटे को सुनहरे भविष्य के लिए सात समंदर पार भेजा था, उसका चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। अमेरिका के कैलीफोर्निया में सड़क हादसे का शिकार हुए करनाल के कोयर गांव के 22 वर्षीय विशाल का 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अंतिम संस्कार कर दिया गया। हादसे में उसका शरीर पूरी तरह से जल गयसा था। डीएनए मैच होने के बाद विशाल को हिंदू रीति-रिवाज से विदा किया गया। अमेरिका के कैलीफोर्निया में 23 जून 2025 की रात को सड़क हादसे में हरियाणा के दो दोस्तों की मौत हो गई थी। जिसमें कोयर गांव का विशाल और कैथल के सिरसल गांव का अरुण जांगड़ा उर्फ रोमी शामिल थे। हादसा उस वक्त हुआ, जब दोनों युवक अपनी जगुआर कार से घूमने जा रहे थे। कार की रफ्तार तेज थी, जो बेकाबू होकर पलट गई। फिर पलटी खाते हुए सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। ट्रक से टक्कर लगते ही कार में आग लग गई, जिसमें दोनों युवक जिंदा जल गए। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया। इसके बाद दोनों को निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। अमेरिका के हिसाब से 7 फरवरी और इंडिया के हिसाब से 8 फरवरी को 7 महीने बाद अमेरिका में ही विशाल का अंतिम संस्कार हुआ।

महाराष्ट्र में बीजेपी को फिर से मिली खुशखबरी

- जिला परिषद चुनाव में लहराया परचम, विपक्ष पस्त

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों में बड़ी जीत हासिल करने के बाद भाजपा ने एक बार फिर से परचम लहराया है। भाजपा को जिला परिषद चुनावों में 145 सीटों पर बढ़त मिली है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना 85 और अजित पवार की एनसीपी 80 सीटों पर आगे है। राज्य में कुल 731 जिला परिषद और 1462 पंचायत समिति के लिए रविवार को मतदान हुआ था। इसमें करीब 2 करोड़ वोटर शामिल हुए थे। पहले ये चुनाव 5 फरवरी को ही होने वाले थे, लेकिन डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के चलते इन्हें टाल दिया गया था और फिर 8 फरवरी को ही मतदान हुआ और आज नतीजे आ गए हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार भाजपा को सांगली, सतारा और पनवेल जैसे इलाकों में बढ़त मिली है। वहीं अजित पवार के गढ़ बारामती में एनसीपी काफी आगे है। माना जा रहा है कि एनसीपी को अजित पवार के निधन के चलते सहानुभूति लहर का फायदा मिला होगा। अजित पवार को पुणे और मराठवाड़ा क्षेत्र के बड़े नेताओं में गिना जाता था। उनकी इस इलाके में अच्छी पकड़ रही है। ऐसे में उनकी निधन के चलते सहानुभूति की लहर पैदा होने की बात भी की जा रही है। जिला परिषद की कुल 731 सीटों के चुनाव में भाजपा सबसे आगे है। उसके सहयोगी शिवसेना और एनसीपी दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के बाद से ही निराशा झेल रहे विपक्ष को एक बार फिर झटका लगा है।

- **सोलापुर और पुणे में एनसीपी आगे,सहानुभूति की दिखी लहर-** सोलापुर में एनसीपी अब तक 24 सीटों पर आगे है। इसके अलावा पुणे में भी उसे बढ़त हासिल हुई है। सोलापुर में कांग्रेस का अब तक खाता भी नहीं खुल पाया है। अब सतारा की बात करें तो भाजपा को यहां 32 सीटों पर बढ़त है। इसके अलावा एनसीपी को 17 और शिवसेना को 10 सीटों पर बढ़त हासिल है।

नाबालिग हिंदू युवती को बहला कर उज्जैन से इंदौर लाए, पुलिस ने ढूंढा

बुर्के में रही युवती, दुष्कर्म के बाद उसके धर्मांतरण की थी तैयारी

इंदौर। यहां धर्मांतरण की साजिश का चौंकाने वाला मामला सामने आया। उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र से लापता 15 साल की किशोरी इंदौर में बुर्का पहने बरामद हुई। किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है।

इस साजिश में किशोरी की मुस्लिम सहेलियों, आरोपी साहेब लाला के परिजन और इंदौर निवासी आकिब ने सहयोग किया। किशोरी को बहला-फुसलाकर साहेब इंदौर लाया था और वहां दो दिन आजाद नगर क्षेत्र में अपने रिश्तेदार आकिब के ही घर में रखा। किशोरी वहां पूरे समय बुर्के में रही। पुलिस ने सीसीटीवी सहित अन्य माध्यमों से किशोरी की खोजबीन की, तो उसके इंदौर में होने की जानकारी मिली।

किशोरी इंदौर में बुर्का पहने बरामद हुई। उसके बयान के आधार पर सामने आया है कि प्रेम जाल में फंसाकर मतांतरण की साजिश थी। दुष्कर्म भी किया गया। चिमनगंज थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि मुख्य आरोपी साहेब उर्फ छोटू और उसके साथी आकिब खान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। किशोरी की सहेलियों पर भी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने उसे बहला-फुसलाकर साजिश की। आरोपियों के परिजन की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

'ग्रूमिंग लव जिहाद' के आरोप

हिंदू जागरण मंच ने 'ग्रूमिंग लव जिहाद' के आरोप लगाए हैं। किशोरी के मोबाइल चैट में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। उसकी मुस्लिम सहेलियों की भी अपराध में भूमिका सामने आई है। उज्जैन पुलिस के अनुसार, आगर रोड क्षेत्र में रहने वाली हिंदू किशोरी को बेगमबाग कॉलोनी के 19 वर्षीय साहेब उर्फ छोटू उर्फ ईमान लाला बहला-फुसलाकर ले गया था।

दोस्त ने बहलाया-फुसलाया

पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि छह महीने पहले अहमद नगर निवासी एक अन्य मुस्लिम नाबालिग लड़के ने पीड़ित किशोरी को बहलाया-फुसलाया था, बाद में उसे छोड़ दिया। वर्तमान केस में आरोपी साहेब लाला उसी लड़के का दोस्त है। पुलिस ने नाबालिग लड़के से पूछताछ की है। उस पर भी कार्रवाई संभव है।

क्या है ग्रूमिंग लव जिहाद

जिस तरह से हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों द्वारा बहला फुसलाकर उनसे दुष्कर्म और उनके धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे अपराधों को संगठित रूप से संचालित करने के संकेत साफ दिख रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों ने इस मामले में ग्रूमिंग लव जिहाद का आरोप लगाया है। ग्रूमिंग लव जिहाद संगठित तरीके से किया जाना वाला अपराध है। किसी नाबालिग लड़की को धीरे-धीरे मानसिक रूप से तैयार कर उसका यौन, आर्थिक और भावनात्मक शोषण किया जाता है। इसके बाद में मतांतरण कराया जाता है।

इस अपराध में और इसकी साजिश में कई लोग शामिल होते हैं। जांच में सामने आया है कि पीड़िता की मुस्लिम सहेलियों ने उसका ब्रेनवाश किया था। इस बारे में पुलिस को मोबाइल पर मैसेज पर भी मिले हैं। इस तरह साजिशन किशोरी को बहला-फुसलाकर घर से ले जाया गया और मतांतरण के लिए उकसाया गया।

नाले में गंदगी और गंदा पानी छोड़ने पर निगम ने लगाया 1.80 लाख का जुर्माना

औद्योगिक इकाइयों को दो दिन में जल प्रबंधन ठीक करने के निर्देश

इंदौर। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नगर निगम लगातार औद्योगिक इलाकों में दौरा और चालानी कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में झोन क्रमांक 17 और झोन क्रमांक 3 में आने वाले सांवेर रोड और पोलोग्राउंड स्थित औद्योगिक इलाकों में नालों में गंदगी और अपशिष्ट पानी छोड़ने वाली औद्योगिक इलाकयों पर चालानी कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार, झोन क्रमांक 17 में आने वाले सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में कार्रवाई की गई। झोनल अधिकारी नरेंद्र कुरील ने बताया कि रविवार को सांवेर रोड स्थित औद्योगिक इकाइयों द्वारा कचरा, गंदगी और अपशिष्ट जल सीधे नाले में छोड़ा जा रहा था। जिसके चलते इन संस्थानों पर कार्रवाई की गई। ये हैं ललित नमकीन पर 50 हजार रुपए, मेघा पॉलिमर पर 35 हजार रुपए, गीतिका प्लास्टिक पर 30 हजार रुपए और उषा ऑर्गेनिक पर 25 हजार रुपए। नगर निगम ने यहां पर 1 लाख 40 हजार रुपए की चालानी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान झोनल अधिकारी नरेंद्र कुरील, सीएसआई आशीष कापसे, उपयंत्री सिद्धांत मेहता सहित विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

झोन क्रमांक 3 में आने वाले पोलोग्राउंड औद्योगिक क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई। झोनल अधिकारी राज ठाकुर ने बताया कि निगम कमिश्नर के आदेश पर झोन 3 के वार्ड 57 में कार्रवाई की गई। इनमें सायनों फार्मा कंपनी द्वारा ईटीपी का उचित संचालन नहीं किए जाने पर 30 हजार का चालान किया गया। कोहिनूर इलास्टिक द्वारा सीवर लाइन में सीधे अपशिष्ट जल छोड़े जाने पर 10 हजार की चालानी कार्रवाई की। यहां कुल 40 हजार की कार्रवाई की गई। निगम अधिकारियों ने औद्योगिक इकाइयों को दो दिन के अंदर अपशिष्ट जल प्रबंधन सिस्टम को ठीक करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

सूचीबद्ध बदमाशों से ब्राउन शुगर जब्त

इंदौर। नशे से दूरी है जरूरी अभियान अंतर्गत पुलिस लगातार मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त पर कार्रवाई की रही है। इसी क्रम में पुलिस ने विभिन्न स्थानों से तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों पर क आपराधिक मामले दर्ज हैं।

आरोपियों से बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर जब्त की है। हीरानगर पुलिस ने आदित्य गेटवे बिल्डिंग के पीछे नाले के पास एमआर-10 रोड पर बाइक (एमपी-09-एस 3744) के साथ खड़े दो युवकों को पकड़ा। पकड़े गए युवकों रोहन कदम निवासी भाग्य लक्ष्मी कॉलोनी एमआर 10 रोड तथा गोपाल उर्फ दीपक अहिरवार निवासी हीरानगर मेन रोड से 13.30 ग्राम ब्राउन शुगर (कीमत दो लाख रुपए) जब्त की है। दोनों आरोपियों पर पहले से अपराध दर्ज है। इसी प्रकार क्राइम ब्रांच ने रेलवे मालगोदाम लक्ष्मी बाई नगर स्टेशन से चिंटू उर्फ चिट्टी निवासी भागीरथपुरा को 102.76 ग्राम मादक पदार्थ के साथ पकड़ा। आरोपी ट्रेनों में सफाई कार्य करता है। उसके खिलाफ एनडीपीएस के 5 तथा मारपीट के 4 केस विभिन्न थानों में दर्ज है। पुलिस तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है।

सिंगर से मारपीट, शराबी युवक फरार

इंदौर। लसूडिया क्षेत्र में शनिवार रात रिसोर्ट में शराबी युवकों ने सिंगिंग प्रोग्राम कर रहे कलाकार के साथ तीन लोगों ने मारपीट कर दी। घटना द एस्केप वर्ल्ड रिसोर्ट की है, जहां गायक निलेश, शादी समारोह और अन्य इवेंट्स में प्रस्तुति देते हैं। वे रिसोर्ट में लाइव परफॉर्म कर रहे थे। तभी उनके साथ वारदात हुई। पुलिस के अनुसार, कुछ युवक नशे की हालत में गाना बंद करवाने लगे। विरोध करने पर युवक ने माइक छीनकर गायक को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उसके साथ मौजूद अन्य युवक भी झगड़े पर उतर आए। रिसोर्ट मैनेजर और स्टाफ ने गायक को बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनके साथ भी अभद्रता की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन युवक बीजेपी के मंत्री का नाम लेकर धमकी देते हुए कार से फरार हो गए। रिसोर्ट प्रबंधन के अनुसार, आरोपी युवक एमपी-09-एएस-4537 नंबर की कार से आए थे, जिस पर बीजेपी सरपंच, ग्राम पंचायत मंडलावदा लिखा हुआ था। गायक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

युवक पर झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप

इंदौर। तेजाजी नगर पुलिस ने एक युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में उसके परिचित युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि आरोपी ने युवती से नाबालिग अवस्था में भी संबंध बनाए थे। पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की है। तेजाजी नगर थाना प्रभारी देवेंद्र मरकाम के अनुसार, इलाके में रहने वाली एक युवती की शिकायत पर शनिवार को रितिक कुशवाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पीड़िता अपनी मां के साथ थाने पहुंची थी। पीड़िता ने बताया कि जुलाई 2025 में आरोपी उसे अपने दोस्त रमन के कमरे पर ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद नवंबर माह में लिबोंदी क्षेत्र में अपने एक अन्य दोस्त के कमरे पर ले जाकर भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में जब पीड़िता ने शादी की बात कही तो आरोपी टालमटोल करने लगा। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी करीब अलग अलग जगह पर ले जाकर 6 बार उसके साथ रेप कर चुका है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

दो स्थानों से 170 पाव देशी शराब जब्त

इंदौर। आबकारी विभाग ने रविवार को अवकाश के दिन भी कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग ने दो स्थानों पर कार्रवाई कर वहां से 95 और 75 इस तरह कुल 170 पाव देशी शराब जब्त की है। कंट्रोलर देवेश चतुर्वेदी और डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में वृत्त प्रभारी जया मुजाल्दे एवं पलासिया प्रभारी प्रियंका रानी चौरसिया ने टीम के साथ जवाहर टेकरी क्षेत्र में कार्रवाई की। यहां कुख्यात तस्कर आनंद चौहान के घर के सामने से दोपहिया वाहन एमपी-09-वीएच-7357 से 95 वहीं दूसरी कार्रवाई में शांति नगर क्षेत्र से सुभाष पवार के घर के सामने से बिना नंबर प्लेट के दोपहिया वाहन की डिक्की से 75 पाव देशी मदिरा बरामद की गई। दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। जब्त शराब एवं वाहनों की कुल कीमत लगभग 1 लाख 45 हजार रुपए आंकी गई है।

युवक की मौत पर परिजनों का पत्नी पर आरोप, शव लिए बिना चली गई

पत्नी ने ही पति के घर से चले जाने की पुलिस को सूचना दी थी

इंदौर। राऊ इलाके में मिले एक युवक के शव की पहचान होने के बाद रविवार को उसके परिजन उत्तर प्रदेश से इंदौर पहुंचे। युवक के पिता और बहन ने उसकी पत्नी और उसके मायके पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि पति की मौत के बाद ही पत्नी अपने रिश्तेदार के साथ मायके चली गई।

राऊ पुलिस के अनुसार, एमराल्ड स्कूल के पीछे 5 फरवरी की देर रात एक युवक ने कथित रूप से आत्महत्या की थी। शव को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी पहचान प्रवीण पिता राजकुमार काछी के रूप में हुई। प्रवीण राऊ की एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करता था और मूल रूप से इटावा का रहने वाला था। प्रवीण की पहचान होने के बाद उसके परिजन रविवार को इंदौर पहुंचे। उन्होंने पत्नी अवनी और उसके मायके पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। पिता राजकुमार ने बताया कि पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद इंदौर में रहने वाले रिश्तेदारों के साथ मिलकर अवनी ने मारपीट की थी। इसके बाद प्रवीण घर से चला गया था। पुलिस ने बताया कि उसी रात अवनी थाने पहुंची थी और उसने पति प्रवीण के लापता होने की सूचना दी थी। पुलिस ने एक दुर्घटना की जानकारी देते हुए पहचान की प्रक्रिया कराई थी।

पति के शव बिना पत्नी गई

रविवार को पुलिस ने प्रवीण के शव का पोस्टमार्ट्म कराया, लेकिन उसकी पत्नी अवनी वहां नहीं पहुंची। पुलिस के मुताबिक, वह प्रवीण के पिता और बहन के इंदौर पहुंचने से पहले ही उत्तर प्रदेश में अपने मायके चली गई थी। वहीं, प्रवीण के पिता और बहन ने पुलिस से पूरे मामले की जांच की मांग की है।

ठेकेदार को ही कॉलोनी का मालिक बनाकर दे दी विकास की अनुमति

प्रशासन के 'कॉलोनी सेल' के अधिकारियों ने अनोखा खेल खेला

इंदौर। जिला प्रशासन के कॉलोनी सेल का गठन कॉलोनाइजर और प्लाट धारकों के बीच विवाद में मध्यस्थता कर कॉलोनी का विकास करने में मदद करना रहा है। वहीं कॉलोनी सेल कॉलोनियों के विकास की राह में रोड़े अटकाकर अपने लक्ष्य से भटक गया। चंद जिम्मेदार अधिकारी अपनी हठधर्मिता के चलते कॉलोनाइजर और प्लॉट धारकों को परेशानी में डालना रह गया। इससे कॉलोनी सेल एक दिखावटी उपक्रम बनकर रह गया।

राऊ तहसील के सोनवाय में बनाई जा रही आवासीय कॉलोनी रिगेन रिजेंसी के भूस्वामी तथा अधिकृत लाइसेंसधारी कॉलोनाइजर 'यंग एंड ग्रो रिटेलर्स' को कॉलोनी का विकास करने की अनुमति मिली थी। उसने शिकायत की है कि उन्होंने जिस ठेकेदार को सोनवाय मेगा टाउनशिप का विकास कार्य करने की अनुमति दी थी, उसने 16 साल तक कॉलोनी का विकास नहीं किया। अब जिला प्रशासन के साथ सांठगांठ तथा फर्जी दस्तावेज बनाकर 10 माह में कॉलोनी का विकास करने की अनुमति कबाड़ ली।

उल्लेखनीय है कि 6 माह में कॉलोनी का विकास करने के लिए जिला प्रशासन को लिखित सहमति देने वाले मूल कॉलोनाइजर को अनुमति नहीं दी गई, बल्कि उनके नाम पर ठेकेदार को उपकृत करने का प्रयास किया गया। कहा जा रहा है कि सारे नियम कानून को ताक में रखकर जिला कलेक्टर को भ्रमित कर कॉलोनाइजर के बदले ठेकेदार को विकास कार्य की अनुमति प्रदान करने में अटल सिटी परिवहन निगम योजना में हुए भ्रष्टाचार के लिए कथित रूप से दोषी प्रदीप सोनी ने यह खेल खेलकर कॉलोनी सेल में हाल ही में पदस्थ रिंकेश वैश्य से उक्त अनुमति पत्र में हस्ताक्षर करवाकर यह गैर कानूनी अनुमति दिलवा दी। जिसके खिलाफ कॉलोनी के वास्तविक मालिक तथा विकास अनुमति प्राप्त अधिकृत लाइसेंसधारी 'यंग एंड ग्रो' के डायरेक्टर परेश छेडा ने सभी विभागों तथा न्यायालय में शिकायत दर्ज कर मामले की जांच कर गुण दोष के आधार पर न्याय की अपील की है।

कांग्रेस नेता की फर्जी शादी का कार्ड वायरल, एफआईआर दर्ज

नेता ने कहा, मेरी शादी नहीं है, लिंक को क्लिक नहीं करें

इंदौर। मेरी शादी नहीं है, कृपया लिंक को क्लिक नहीं करें। यह अपील कांग्रेस नेता सदाशिव यादव ने सोशल मीडिया पर उनकी शादी का कार्ड वायरल होने पर अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अन्य शुभचिंतकों से की। मामले में यादव ने तेजाजी नगर थाना तथा साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस के अनुसार, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता उस समय असमंजस में पड़ गए, जब सोशल मीडिया पर उनकी शादी का डिजिटल निमंत्रण पत्र अचानक वायरल होने लगा। हैरानी की बात यह रही कि यह कार्ड हजारों लोगों के मोबाइल तक पहुंच गया, जबकि नेता की ओर से ऐसी किसी शादी की कोई बात ही नहीं है। कार्ड में शादी की तारीख 24 फरवरी लिखी गई है। इसके साथ संदिग्ध लिंक भी जोड़ा गया है, जिसे ह्विशेष निमंत्रणह्व के नाम पर खोलने के लिए कहा जा रहा है।

मोबाइल डाटा हैक किया

मामले की जानकारी मिलते ही यादव ने स्पष्ट किया कि उनकी कोई शादी तय नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट या मोबाइल डेटा हैक किया गया है। यह घटना उनकी छवि धूमिल कर उन्हें बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। कुछ दिन पहले साइबर सेल और क्राइम ब्रांच ने शादी के फर्जी निमंत्रण पत्र को लेकर एडवाइजरी जारी खी थी। इसके बाद भी कुछ लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही क्लिक को खोलकर ठगी के शिकार हो रहे हैं।

अवैध संबंध के चलते की हत्या, आरोपी धराया, कॉलेज के परिसर में मिली लाश

रात में महिला पर हमला हुआ, इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई

इंदौर। शनिवार को परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के पीछे सुगनी देवी कॉलेज की पीछे मिली महिला लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने महिला के कथित पति मुकेश कोरी निवासी को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। हत्या के पीछे अवैध संबंध की बात सामने आई है।

पुलिस को शनिवार सुबह सूचना मिली थी कि कॉलेज परिसर में अर्धनग्न अवस्था में महिला की लाश पड़ी है। पुलिस के मुताबिक, कुछ दिनों से मृतक महिला आरोपी के साथ रह रही थी। दोनों नशे के आदी थे और अक्सर साथ में समय बिताते थे। घटना वाली रात आरोपी महिला को मैदान में लेकर गया, जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर पत्थर से महिला पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल महिला को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई।

दुष्कर्म की धाराएं जुड़ेंगी- एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में अपराध कबूल कर लिया है। प्रारंभिक जांच में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यदि आवश्यक हुआ तो दुष्कर्म से संबंधित धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। मृतक महिला के तीन बच्चे बताए जा रहे हैं, लेकिन अब तक परिवार का कोई सदस्य सामने नहीं आया है। पुलिस महिला की पहचान और परिजनों की तलाश में जुटी हुई है।

दो घंटे बाद फिर पहुंचा- आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह और मृत महिला दोनों मजदूरी करते थे। कई बार दोनों साथ में शराब पीते थे, वहीं से उनकी दोस्ती हुई थी। हत्या के पहले उसने रात 3.30 बजे महिला से संबंध बनाए थे, फिर पत्थर मारकर भाग निकला था। रविवार सुबह 5.30 बजे वह महिला को देखने पहुंचा था, तब महिला अचेत अवस्था में पड़ी थी। महिला को देखकर वह इधर-उधर भटकता रहा। हत्याकांड के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर 7-8 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने आरोपी मुकेश भी शामिल था।

संपादकीय

राष्ट्रीय न्यायिक नीति की दरकार

देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रीय न्यायिक नीति का मुद्दा एक बार फिर उठाया है, जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। हालांकि यह मुद्दा पहले भी उठता रहा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा इसे धार देने से नई बहस शुरू हो गई है। भोपाल की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में सम्पन्न सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों के दो दिनी सम्मेलन में कई अहम बातें हुईं, जिनमें न्यायिक नीति के अलावा सरकारों और अन्य के बीच सालों चलने वाले मुकदमों पर अंकुश लगाने के लिए पहले स्वयं कोर्ट ही ऐसे मामले में दोनो पक्षों में आपसी समझौते की पहल आदि शामिल है। इस बात पर सभी न्यायाधीश एकमत दिखे कि केंद्र और राज्य अदालतों में बढ़ते लंबित मामलों की सबसे बड़ी वजह सरकारी केस हैं। यह आम राय दिखी कि सरकारों को वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सरकार की ओर से केस दायर किए जाने पर अब जज ही उन्हें कहें कि पहले आपसी समझौते से समाधान के विकल्प तलाशें, उसके बाद ही अदालत का रुख करें। सरकारी पक्ष को यह भी कहा जाएगा कि वर्षों तक अदालतों में केस लड़ने से होने वाले नुकसान के बजाय सरकारें मामूली नुकसान स्वीकार कर तुरंत समाधान की दिशा में आगे बढ़ें। अगर मध्यप्रदेश की ही बात करें तो मप्र हाई कोर्ट में लंबित 65 से 70% केस ऐसे हैं, जिनमे मप्र शासन या फिर केंद्र पार्टी है। इसमें कुछ केस ऐसे भी हैं, जो मप्र शासन या फिर केंद्र ने ही दायर किए हैं। अदालतों में लंबित मामलों में 10 से 15% सर्विस मैटर हैं। सरकार सबसे बड़ी जमीन मालिक भी है, इसलिए कई सिविल विवाद उसी से जुड़े हैं। ऐसे मामलों को कोर्ट की बजाय मध्यस्थता से सुलझाया जाए, तो निपटारा तेज होगा। न्यायपालिका स्तर पर शुरुआत होने से प्रक्रिया और तेज हो सकती है। इसी प्रकार फौजदारी मामलों में लंबित केसों का बोझ कम करने के लिए यह रणनीति तय की गई कि 7 साल तक की सजा वाले मामलों को सुनवाई में प्राथमिकता दी जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में माना गया कि देश को अब एक राष्ट्रीय न्यायिक नीति की जरूरत है। यह नीति न्यायपालिका को एकीकृत, संगठित और मजबूत बनाएगी। साथ ही अदालतों को तेज, सरल, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने में मदद करेगी। न्यायाधीशों ने देश में बढ़ते मीडिया ट्रायल पर भी गंभीर चिंता जताई गई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने साफ कहा कि न्याय सिर्फ अदालत में होना चाहिए, मीडिया में नहीं। जजों को मीडिया में चल रही चर्चाओं के प्रति संवेदनशील तो होना चाहिए, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। कहा गया कि न्याय का फैसला कोर्ट में होना चाहिए, टीवी स्टूडियो में नहीं। मीडिया ट्रायल से निर्दोष व्यक्ति की छवि खराब होती है और इसे रोकना जरूरी है। सम्मेलन में डिजिटल व भाषाई समावेशनः सम्मलेन में ई-कोर्ट, डिजिटल फाइलिंग और स्थानीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देकर न्याय को आम जनता के और करीब लाने का संकल्प लिया गया। इसमें दो राय नहीं कि सरकार को न्याय के मामले में एक राष्ट्रीय नीति घोषित करनी चाहिए ताकि इस संदर्भ में पूरे देश में एकरूपता रहे। राष्ट्रीय न्यायिक नीति सरकार की न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और अदालतों की न्यायशीलता को सुनिश्चित करेगी। इसी प्रकार राष्ट्रीय न्यायिक सेवा की मांग भी बरसों से की जा रही है। निचली अदालतों में इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। अभी हर राज्य में अलग-अलग तरह से जजो की भर्ती होती है। देश में न्यायिक सुधार समय की मांग है। सरकार को इस पर जल्द कदम उठाना चाहिए।

यूजीसी नियमों के पीछे आखिर राजनीति क्या है?

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026, जिसे शिक्षा व्यवस्था में समानता का नियम बताया जा रहा है और समाज के एक हिस्से के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। जो विरोध करने वाले मित्र हैं उनका यह तर्क है कि इस कानून में जो कमेटियां जांच पड़ताल के लिए बनाई जा रही हैं, उनमें सवर्ण समाज का कोई घोषित प्रतिनिधि नहीं है, दूसरा यह कि यह तबका यह मान रहा है कि इसका अर्थ सवर्ण समाज के लिए ही जातीय भेदभाव या अपमान के लिए पहले से ही दोषी मानना है। क्योंकि उनके अनुसार सवर्ण समाज के प्रतिनिधि को इसमें नहीं रखा गया है। इस विरोध में करणी सेना, धर्म गुरु भी शामिल हुए हैं। एक महामंडलेश्वर श्रीगिरी महाराज ने तो 23 जनवरी से दिल्ली में आमरण अनशन करने की घोषणा और अपनी जान देने की भी घोषणा की थी।

उन्होंने अपने वीडियो रिकॉर्ड बयान में इस कानून के लाने वालों के लिए काफी श्राप भी दिए हैं उनके श्राप कितने प्रभावी होंगे यह मैं नहीं जानता हूं। उनके उपवास/अनशन के बारे में भी कोई खबर अभी तक नहीं मिली है। साधु समाज की ओर से भी उनके पक्ष में या विपक्ष में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। करणी सेना और कुछ संगठनों ने अवश्य ही कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया है। वैसे भी करणी सेना पिछले कुछ वर्षों से काफी चर्चा में है और जहां तहां उनका आक्रामक व्यवहार सामने आ रहा है। इसकी शुरूआत राजस्थान में पद्मावती फिल्म के निर्माता के साथ मारपीट हुई थी और अब यह देश के विभिन्न इलाकों में जाति आधार पर धरना, प्रदर्शन विरोध आदि करके अपनी ताकत की पहचान बना रहे हैं। यह मुख्यतः राजपूतों का संगठन है और अभी कुछ दिनों पहले हरदा में एक कार्यक्रम के बाद उन्होंने यह भी घोषणा की है कि वह अब चुनाव लड़ेंगे। यह कोई आकस्मिक घटना या कोई योजना है, इसकी पड़ताल की जानी चाहिए।

जिस कानून के बारे में अभी काफी तेज चर्चा चल रही है, उस कानून के पहलुओं को और पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। कुछ वर्ष पहले जब हैदराबाद के एक नौजवान रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी और उसकी वजह यह बताई गई थी कि उनके विरुद्ध झूठी शिकायत के आधार पर जो विद्यार्थी परिषद के लोगों ने की थी, उनकी छात्रवृत्ति रोक दी गई थी। दरअसल रोहित वेमुला के ऊपर विद्यार्थी परिषद के एक विद्यार्थी ने मारपीट का आरोप लगाया था और उस संबंध में शिकायती पत्र वहां के सांसद जो उस समय केंद्रीय मंत्री थे और स्वतः पिछड़ी जाति के बघेल समाज से थे, को आवेदन भेजा था। जैसे कि एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि आमतौर पर प्राप्त आवेदनों की जनप्रतिनिधि या मंत्री संबंधित विभाग को जांचकर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज देते हैं। वैसा ही एक पत्र मंत्री की ओर से उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति के पास गया था। कुलपति ने उसके बाद जो भी जांच की हो या जांच की प्रत्याशा में रोहित वेमुला की छात्रवृत्ति रोक दी थी और कुछ दिन रोहित वेमुला छात्रावास में अपने विश्वविद्यालय के अध्यापक के पास रहे थे। हालांकि बाद में उन मंत्री को भी दोबारा मंत्रिमंडल विस्तार में स्थान नहीं मिला था। अगर इसका आधार रोहित वेमुला की घटना थी, तो मैं समझता हूँ कि इन मंत्री के साथ यह अन्याय था। इन मंत्री से मेरी मुलाकात हुई है और वह एक सीधे-साधे व्यक्ति हैं। उन्होंने कोई दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई को नहीं लिखा, बल्कि एक सामान्य पत्र अग्रेषित किया था। परंतु इतना दबाव मीडिया के माध्यम से बनादिया गया कि जैसे उन्होंने ही वेमुला को निकालने का आदेश दे दिया हो।

महिला को पीड़ित पक्ष के रूप में शामिल किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि संसदीय समिति में किसी बीजेपी के सांसद ने यह कहा कि जब जातीय भेदभाव को मिटाने की बात हो रही है और कानून बनाया जा रहा है तो इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को शामिल करना चाहिए। श्री दिग्विजय सिंह ने बतौर अध्यक्ष इसका समर्थन किया और संसदीय समिति ने उनके हस्तक्षेप पर सर्वसम्मति से इस संशोधन को स्वीकार किया। जो अब इस विनियम के रूप में 13 जनवरी को 2026 को लागू हुआ है। इस विनियम के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिकार दिए गए हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के तमाम विश्वविद्यालयों को अपने-अपने क्षेत्र में समानता के व्यवहार के लिए और विषमता को, या जातीय भेदभाव और अपमान को, मिटाने के लिए कमेटियां बनाने का, उसकी प्रक्रिया का, उसके दंड नियम का प्रारूप सभी विश्वविद्यालयों को भेजा है। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना भारत के राज्यपत्र में 13 जनवरी को प्रकाशित हुई है इसको मैंने पढ़ा है। इसको पूरा पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी पक्ष को इससे कोई शिकायत होना चाहिए। जो परिभाषाएं नियम 3 में दी गई हैं उसके एक (ख) में लिखा गया है कि पीड़ित व्यक्ति का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास विनियम के अंदर अंतर्गत शिकायतों के संबंध में कोई शिकायत है। जाति आधारित भेदभाव का अर्थ भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जातीय या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। जो कमेटी किसी शिकायत के प्राप्त होने के बाद जांच के लिए बनाई जा रही हैं उसके अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलपति या संस्था के प्रमुख होंगे। जो सदस्य इस समिति में शामिल होंगे, यानि जांच समिति में उसमें संबंधित शिक्षा संस्थान के तीन प्रोफेसर, तीन प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य, उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी, शिक्षक के अतिरिक्त व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक, समाज के प्रतिनिधि, दो छात्र प्रतिनिधि, जिनका नामांकन उनकी गतिविधियों के आधार पर किया जाएगा, विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल किए गए हैं। अब जांच समिति के इस संगठनात्मक ढांचे को किसी जाति तक सीमित नहीं किया गया है और यह जो सदस्य हैं इन्हें नामजद करने वाला नाम किसी अधिकृत व्यक्ति किसी भी समूह से चाहे वह सवर्ण हो या वह अवर्ण, नामजद कर सकता है।

मुझे आश्चर्य है कि हमारे सवर्ण समाज के मित्र जिन्हें इस विनियम के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था और पीड़ितों के साथ-सहारा बनना चाहिए था वह क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? करणी सेना क्षत्रियों का संगठन है और क्षत्रियों का धर्म ही कमजोर की रक्षा है तो क्षत्रिय समाज कैसे इसका विरोध कर सकता है। भगवान राम क्षत्रिय थे और सदैव कमजोर के पक्ष में खड़े हुए। फिर अगर कोई अन्याय की घटना कमेटी के द्वारा की जाती है तो उसके खिलाफ अपील का प्रावधान है और न्यायपालिका के दरवाजे तो खुले हुए हैं। बेहतर तो यह होता कि इन नियमों के व्यावहारिक प्रयोग को कुछ समय देखा-परखा जाता और प्राप्त परिणामों के आधार पर इनकी पुष्टि, इनका मूल्यांकन या इनका विरोध होता। परंतु बगैर किसी प्रयोग के ही विरोध करना और वह भी तार्किकता का ना हो तो आश्चर्यजनक है।

इस विनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पक्ष पीड़ित है। तो निर्णय के 30 दिन के भीतर ओम्बड्स मैन (लोकपाल) के सामने अपील कर सकता है। वह और एमिकस क्यूरी की नियुक्ति कर सकते हैं। यह भी प्रावधान किया गया है कि 30 दिन के भीतर ऐसी अपील का निराकरण करने के सब उपाय होने चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उन संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। जिसमें इन विनियमन नियमों का पालन नहीं करने का पालन नहीं होता है या दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर विनियम की बनावट को लेकर कोई शिकायत भी थी या कोई संदेह था तो क्या यह बेहतर नहीं होता की आपत्तिकर्ता पक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों से मिलते सत्ताधारी राजनीतिक दल भाजपा और अन्य सभी संसदीय समिति के सदस्यों या उनके दलों के नेताओं से मिलते। उन्हें अपना पक्ष बताते और मिलजुल कर कोई हल सर्वसम्मति से निकालने का प्रयास करते। क्योंकि संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से हल निकालने यह विनियम पास किया है। यानी यह तो समूची संसद का बौद्धिक निर्णय है और समूची संसद के बौद्धिक क्षमता को नकारना, उसकी आलोचना करना, उसके खिलाफबयान बाजी करना, कैसे उचित ठहराया जा सकता है। क्योंकि यह नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में बने हैं। अतरू अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास विचारण हेतु पहुंच गया है। एक मित्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट विचार कर इस पर निर्णय करेगा ताकि समाज में तनाव पैदा ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल विनियम क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सी.जे.आई. ने तो याचिका पेश होने से पहले ही कह दिया था कि वे इस याचिका को सुनने के इच्छुक हैं तथा अगले ही दिन याचिका पेश होते ही उन्होंने स्थगन आदेश भी दे दिया। इस प्रकरण पर शीर्ष अदालत की इस सक्रियता को देखकर देश आशान्वित है कि अब शायद सभी प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही शीघ्रता से निर्णय करेगा। एससी,एसटी और ओबीसी के लोग और छात्र भी इस विनियम के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, जुलूस और प्रदर्शन कर रहे हैं, और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि कुलपति अगर सवर्ण वर्ग से होगा तो इन वर्गों को न्याय कैसे मिलेगा? वह दूसरे प्रकार की आशंका प्रकट कर रहे हैं कि कुलपति अगर सवर्ण होगा तो क्योंकि वह विश्वविद्यालय का प्रमुख शासक होता है और उसके दबाव में शिक्षक रहते हैं अतः वह जैसा चाहेगी वैसा फैसला कर लेगा तथा इसका लाभ उन अपराधियों को मिलेगा जो भेदभाव करते हैं और सवर्ण समाज से हैं। मैं अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी के छात्रों या नौजवानों कि इस आशंका से भी सहमत नहीं हूँ।

किसी भी व्यक्ति या संस्था के बारे में पूर्व धारणा बनाना कि वह गलत ही करेंगे यह मानव के प्रति मूल अविश्वास है। यह भी नहीं भूलना चाहिए की देश में कितने ही सवर्ण जातियों में जन्मे लोग ऐसे हुए हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के पक्ष में, महिलाओं या दिव्यांगों के पक्ष में, जमकर खड़े हुए और उनमें चेतना पैदा की है। गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय थे, जयप्रकाश और लोहिया जी भी सवर्ण थे, मामा बालेश्वर दयाल भी ब्राह्मण थे, और ऐसे देश के कितने ही नाम गिनाए जा सकते हैं जहां सवर्ण जाति के घर में जन्मे लोगों ने पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं को न्याय दिलाने, उनमें चेतना पैदा करने में अपना सारा जीवन लगा दिया। आजादी के पहले महात्मा गांधी थे तो आजादी के बाद डॉ. राम मनोहर लोहिया थे। जिन्होंने कहा था की पिछड़े पांवें 100 में 60 और उस जमाने में हम नौजवानों से अपील की थी कि तुम सवर्ण लोगों को समाज में परिवर्तन के लिए खाद बनना चाहिए। लोहिया ने कहा था कि योग्यता अवसर से आती है और इसलिए पहले योग्यता, फिर अवसर का सिद्धांत गलत है। महात्मा गांधी ने तो डॉ. बी आर अंबेडकर के द्वारा उनकी आलोचना करने पर कहा था कि हमारे पुरखों ने इनके साथ इतने अन्याय किए हैं कि हमें गाली तो क्या अगर ये हमें पीटते भी हैं तब भी हमें उसे चुपचाप सहन कर अपने अतीत की गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए। कुल मिलाकर दोनों ही पक्ष केवल आशंका पर मैदान में है। इन आशंकाओं को क्या पीछे से कोई और हवा दे रहा है? यह भी विचारणीय है।

कई प्रबुद्ध लोगों ने और विशेषकर के सवर्ण और अवर्ण जातियों के प्रबुद्ध जनों के विचार मैंने सुने हैं, बातचीत भी की है और एक संभावना यह भी उभरी हैं कि यह सब सत्ता के शीर्ष से प्रायोजित ड्रामा है ताकि सवर्ण नौजवान और सवर्ण संगठन इस विनियम के आधार पर सत्ता पक्ष का विरोध करें और सत्ता पक्ष को बगैर कहे और बगैर मांगे पिछड़े वर्ग- एससी-एसटी-महिला आदि का समर्थन प्राप्त हो जाए तथा इन वर्गों के बीच में क्रांतिकारी सिद्ध हो जाए।

भगवा बनाम भगवा, संत बनाम संत, कब होगा अंत

राजनीति

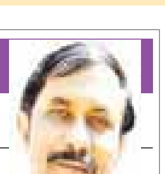

ऋतुपर्ण दवे

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

यह सच है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता ज्यादातर उत्तरप्रदेश से ही होकर निकलता है। यह भी सच है कि भले ही देश में नरेन्द्र मोदी को लेकर कोई विकल्प न हो लेकिन उनके उत्तराधिकारी के रूप में अघोषित रूप से योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले आता है। वहीं अक्सर सियासत में कहे-अनकहे ऐसे दांव-पेंच चले जाते हैं या हो जाते हैं जिससे आसान राहें भी मुश्किलें बढ़ाती नजर आने लगती हैं। फिलाहाल उत्तरप्रदेश में चुनावी सरगर्मी तो नहीं है लेकिन राजनीतिक सरगर्मी ने पहले पौष की कड़कड़ती ठण्ड और अब माघ की जाती ठण्ड में भी जबरदस्त और इतनी कि लू सरीखे सियासी तपन का अहसास जरूर करा दिया।

दरअसल, उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के प्रमुख स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का 28 जनवरी को माघ मेला में स्नान किए बिना लौटना भले ही एक धार्मिक मामला हो। लेकिन वास्तव में सियासी ज्यादा रहा। नए वर्ष की शुरुआत में ही उत्तरप्रदेश में 'भगवा बनाम भगवा' का मुद्दा जबरदस्त राजनीतिक और धार्मिक विमर्श का अहम मुद्दा रहा। लेकिन इसका यह आशय नहीं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान और पालकी सहित जाने की जिद और प्रशासन के नहीं जाने देने से उत्पन्न विवाद इतना बड़ा तूल पकड़ेगा, इसका जनमानस को जरूर अंदाजा नहीं रहा। हाँ, सियासतदारों को जरूर बैठे, बिठाए बड़ा मौका मिल गया।

वास्तव में अविमुक्तेश्वरानंद अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वो किसी को भी नहीं छोड़ते ऐसी स्थिति में उनसे इस टकराहट को असाधारण माना जा रहा है। यदि वास्तव में प्रयागराज मेला प्रशासन चाहता तो इसे टाल सकता था लेकिन कहते हैं न कि राजनीति में लिए गए छोटे से छोटे फैसलों के दूरगामी परिणाम मतलब भरे होते हैं। हुआ भी वही। अब लोग भले ही यह कहें कि सरकार ने गलत किया या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। लेकिन सच तो यह है कि इसे प्रशासन की चूक या भूल भी कहना बेमानी होगा।

एक ओर रूठे हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी ने शंकराचार्य विवाद के दौरान ही सीधे नाम न लेकर, सनातन धर्म की आड़ में राष्ट्रविरोधी या सनातन विरोधी एजेंडा चलाने

वालों को 'कालनेमि' कह दिया। जाहिर है इशारा अविमुक्तेश्वरानंद पर था। बाद में प्रयागराज में जो घटा, उसे देश ने देखा। बात असली और नकली शंकराचार्य तक जा पहुंची तो भला अविमुक्तेश्वरानंद कैसे चुप रहते? उन्होंने भी सीधे-सीधे आदित्यनाथ से टकराने की रणनीति अपना ली। इस बीच प्रशासन ने शंकराचार्य को नोटिस पकड़ा दिया कि 18 जनवरी को त्रिवेणी संगम में जबरदस्ती घुसने के प्रयास से भगदड़ मच सकती थी। इतना ही नहीं यह तक पूछ लिया कि क्यों न उन्हें भविष्य के मेलों में भाग लेने से रोक दिया जाए? तल्खी और तब बढ़ी जब अगले नोटिस में मेला अधिकारियों ने 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए शंकराचार्य की उपाधि पर ही सवाल उठा, विवाद को गहरा दिया। ऐसा देश ने पहली बार देखा।

शह-मात के इस खेल में स्वामी अविमुक्तेश्वरनद ने अपने जवाब में उल्टा पूछ लिया कि 'ना प्रशासन, ना उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री, और ना ही देश के राष्ट्रपति तय करेंगे कि कौन शंकराचार्य हो? हालांकि शंकराचार्य पर आरोप लगे कि वो कांग्रेसी विचारधारा के हैं। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया और कई बड़े नेताओं ने मुलाकात की। निश्चित रूप से वक्त के साथ शंकराचार्य विवाद राजनीतिक रूप ले चुका था। जिसमें कई मोड़ आए। एक ओर जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी विश्वास व्यक्त किया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और उत्तरप्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकलेगा वहीं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे स्नान करने की अपील की और कहा कि मैं ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनसे प्रार्थना है कि वह स्नान कर इस विषय का समापन करें। लेकिन यह हो न सका।

बस यहीं से जो मामला भगवा बनाम भगवा था उसे पार्टी लाइन की ओर भी समझा जाने लगा। उत्तरप्रदेश में भाजपा की गुटबाजी जगजाहिर है। यह तब और समझ में आई जब बीते महीने 30 जनवरी को महोबा विधायक में भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत और योगी कैबिनेट के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आपस में तकरार हो गई। मंत्री एक कार्यक्रम से लौट रहे थे कि दोपहर करीब साढ़े तीन बजे विधायक ने 100 ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर उनका रास्ता रोक लिया और 100 गांवों में पानी न पहुंचने और पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने पर नाराजगी जताई। इसी तरह केशव प्रसाद मौर्य का बयान आना कोई सामान्य घटना नहीं है। बहरहाल इस पर भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रया नहीं आई लेकिन मौर्य का निवेदन हाईकमान का रुख माना जा रहा है तो ज़िला प्रशासन का ऐक्शन योगी सरकार का कदम। यकीनन ऐसी घटनाओं के पीछे बड़ी सियासत होगी जो आम लोगों की समझ से बाहर है। वैसे सबको पता है कि कैसी कवायद से योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद उनकी कार्यप्रणाली से उनका कद लगातार बड़ा होता चला गया।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 28 जनवरी को दुखी मन से वाराणसी से विदा ली और बिना स्नान लौट गए। घटना को अकल्पनीय बताया। हालांकि संतों में भी दो परस्पर विरोधी गुट बन गए। वही अविमुक्तेश्वरानंद भी कमर कस के तैयार हैं। उन्होंने उत्तरप्रदेश में गाय को राजमाता का दर्जा दिलाने और गौ हत्या रोकने के लिए 40 दिनों की मोहलत दी जिस पर संत परमहंसाचार्य ने इसे राजनीति से प्रेरित बता कहा कि केवल गाय नहीं पूरा गौवंश (बैल, बछड़ा, नंदी) को राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो तभी पूर्ण गौ-रक्षा संभव है। बहरहाल योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की इस जुबानी जंग को लोग ऊंचे दर्जे की राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में कुछ इसे केन्द्र और राज्य के बीच का मसला समझते हैं तो कुछ इसे योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद से जोड़कर देख रहे हैं। बहरहाल ऐसी घटनाओं से अपने आप ही समझ आता है कि माजरा क्या है? अब देखना है कि अगले वर्ष उत्तरप्रदेश में चुनाव हैं ऐसे में भगवा बनाम भगवा और संत बनाम संत की इस लड़ाई में किसे, कितना नफा-नुकसान होता है क्योंकि इतने बड़े मसले पर भाजपा केन्द्रीय नेतृत्व या पार्टी की चुप्पी भी बड़ा इशारा जरूर करती है।

हर वसंत फूलों में जो खिलखिलाते हैं

बालकवि बैरागी की जयंती

लाल बहादुर श्रीवास्तव

बालकवि बैरागी वह शख्सियत हैं जिनका नाम लेने से शहर की पहचान हो जाया करती है। बैरागीजी एक कवि के साथ साथ कुशल राजनितिज्ञ,एक श्रेष्ठ संचालक,कुशलवक्ता और श्रेष्ठ गद्य लेखक के साथ साथ बच्चों के बालकवि भी थे।आपने बच्चों के लिए कई गीत कविताएं लिखी जो बच्चों के जीवन के लिए प्रेरणा बनी है। बच्चों के लिए रानी और लाल परी फिल्म के मनमोहक गीत आपने लिखे थे। सन् 1945 में मात्र 14 वर्ष की नन्ही उम्र में कांग्रेस का तिरंगा थामा तो बस थाम ही लिया। स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही नहीं रहे परन्तु अपनी ओजस्वी कलम से कई क्रांतिकारी गीत लिखे जो स्वतंत्रता के साक्षी बने। आपकी निष्ठा,अकम्प,अविचल,अनवरत और अनंत रही।

बैरागीजी एक मात्र ऐसे व्यक्ति नहीं,व्यक्तित्व थे जिनकी अखिल भारतीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति आज भी है।बैरागीजी हिंदी भाषा,लोक भाषा मालवी के श्रेष्ठ कवि थे। जिनकी काव्य यात्रा श्रृंगार और अंगार के सौपानो को पार करते हुए , मानवता के लिए सदैव समर्पित रही है। वे मंचजयी कवि रहे हैं कई घंटे श्रोताओं को अपनी कविताओं से बांधे रख सकते थे। ऐसे कई प्रसंग है जब बैरागीजी ने अपनी रचनाओं से देर रात सुबह की भोर तक समा बांधे रखा।

बैरागीजी का प्रबल सौभाग्य रहा है कि प. नेहरूजी और इंदिरा जी दोनों ही इन्हें नाम से जानते थे।और समय समय पर अपने महत्वपूर्ण कार्य बैरागीजी से सम्पादित करवाते थे। गांधीवादी होकर वे गांधीजी शास्त्रीजी एंव साहित्यिक गुरू शिवमंगल सिंह सुमन से प्रभावित थे। बैरागीजी का मालवी फिल्मों में बड़ा योगदान रहा है।मालवी की पहली फिल्म भादवा माता आपकी प्रेरणा से सन 1973 में बनी थी। मुकुंद त्रिवेदी इसके निर्माता निर्देशक थे। संगीत बालमुकुंद जी के नाम से बैरागीजी और मुकुंद भाई त्रिवेदी ने दिया था। बालकवि से बाल और मुकुंद भाई से मुकुंद लेकर बालमुकुंद नाम से संगीतकार का नाम रखा था। रेशमा शेरा फिल्म के लिए 1970-1971 में संगीतकार जयदेव मुम्बई से चलकर भोपाल आए तब बैरागीजी मध्यप्रदेश शासन में सूचना और प्रकाशन विभाग में राज्यमंत्री थे। अपने पुतली घर आवास में रात्री 10 से 12 बजे के बीच आपने लोकप्रिय गीत तू चंदा मैं चांदनी लिखा था। जिसे लताजी ने गाया था। बैरागी जी के लगभग 70 गीत जयदेव जी की डायरी में गुमनाम चले गये । ये मुझे दिए साक्षात्कार में दादा बैरागीजी ने बताया था। नहीं तो कई गीत इनमें से आज हम सबकी जुबां पर होते। बैरागीजी के मालवी गीतों में बाजे रे ढ़ोल बाजे,आई रे बरखा रानी,,लखारा,बादरवा अईग्या कणप्रिय गीत है।साथ ही पनिहारिन मालवी की कालजयी कविता है।

हिंदी राष्ट्रभाषा के विनम्र सेवक के रूप में देश विदेश में पहचाने जाने वाले बैरागीजी ओजस्वी कवि रहे है। हिंदी सेवा के अमूल्य योगदान के लिए सैकड़ों बार बैरागीजी सम्मानित विभूषित किये गये। बैरागीजी जब तक रहे साहित्य और राजनीति में रहते हुए एक सरस्वती पुत्र का दायित्व धर्म बखूबी निभाया। साहित्य को धर्म,राजनीति को कर्म मानते हुए इन दोनों की लक्ष्मण रेखा को बहुत बारिक मानते हुए राजनीति को कभी कविता का विषय नहीं माना। उनका मानना था कि उनकी सरस्वती ने कभी राजनैतिक आभा को कालिख नहीं लगने दी।बैरागी जी के साहित्य पर कई विद्यार्थियों ने पी.एच.डी की उपाधि प्राप्त कर अपने को गौरवान्वित महसूस किया। आज 10 फरवरी की बसंत बेला है और दादा बैरागीजी का पावन 96वां जन्म महोत्सव। ये दिन उनके साहित्यकार मित्रों स्नेहियों के लिए एक उत्सव साहित्य पर्व भी है । उनसे मिलने मनासा जाते और दादा के आत्मीय आशीषों से हम पुलकित हो जाते, खूब ठहाके लगाते।दादा आज भी हमारे करीब उतने ही है जितने पहले। दादा हर बसंत हम सभी के साथ खिलखिलाते रहेंगे महकते फूलों की तरह ।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा अग्निबाण पब्लिकेशन, 121, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

कविता, कॉफी और विश्वास कौन हैं ये तीनों ?

व्यंग्य

डॉ. महेन्द्र अग्रवाल

वह बुद्धिजीवी थे इस नाते उन्हें कॉफी से प्रेम था। चाय को वह सर्वहारा वर्ग का पेय मानते थे। स्वभाविक रूप से हर बुद्धिजीवी भले ही वह स्वयं सर्वहारा वर्ग में हो,पर अपने को उस वर्ग से अलग मानता समझता है। कारण बस उसके संस्कार ही समझ लो,और क्या कहें? उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। बुद्धिजीवी होने और कॉफी से अभिन्न रूप से जुड़े होने के कारण वह कविता से भी जुड़ गये थे,ऐसा वो मानते थे।जबकि उनके साथियों व शहरवासियों की राय इस मामले में कुछ भिन्न थी। अब न बताने की बात पर्दे में ही रहे तो अच्छा है। वैसे भी किसी कॉफी हाउस में किसी बुद्धिजीवी को कॉफी पीते हुए कविता ही अधिक सूझती है,इसमें भी दो मत नहीं। यदि कॉफी के साथ कॉफी हाउस में कविता न हो तो वह काहे का बुद्धिजीवी?

इसी परंपरा के निर्वहन में सुप्रसिद्ध लेखक कवि कथाकार उपन्यास सम्राट घासीलाल कॉफी के घूंट भरते हुए किसी नई कविता पर विचार कर रहे थे पर कविता दो-तीन पंक्तियों के बाद ही उन्हें अंगूठा दिखाकर भाग खड़ी होती ।वह फिर जाल फेंकते,इधर-उधर से एक दो अधकचरे विचार पकड़कर उन्हें खड़ा करने की कोशिश करते,रचना प्रक्रिया की झोली खोलकर अभ्यस्त मदारी की तरह पूरा सामान निकालते तब तक कविता फिर किसी नए डरे हुए जमूरे की तरह भाग खड़ी होती। दरअसल कविता के साथ विश्वास का संकट गहरा रहा था। कविता के सम्मुख उनका विश्वास एक नए संकट की तरह खड़ा हो गया था। कविता उन्हें बुद्धिजीवी मानने को ही तैयार नहीं थी।

कॉफी से उसे एलर्जी थी। वह साधारण वर्ग की सीधी सादी महिला सी थी जिसे कॉफी कड़वी लगती थी। फिर वह इस कॉफी के कड़वे घूंट के साथ उनकी बातों के जाल में क्यों आती? कवि को चाहिए था कि कवि कर्म से पहले उसे अपने विश्वास में लेते फिर कागज पर उतारते या शायद उससे पहले अपने दिल में और फिर कागज पर।

कवि या उस कथित बुद्धिजीवी के आठ दस असफल प्रयासों के बाद कवि का कविता से भी झगड़ा होने लगा। कविता के साथ-साथ झगड़ा इतना बढ़ा कि कवि के साथ मुंहवाद करते-करते रचना प्रक्रिया को सांस उठी और अगले ही क्षण वह रचना अलग हो गई और प्रक्रिया अलग। अब तो मुसीबत और बढ़ गई,कवि रचना से बहस करने लगा तो प्रक्रिया रूठ गई। फिर वह इतना गुस्से में आई कि कवि को ललकारने लगी। बोली रचना के सामने मुझे छोटा समझते हो? मेरे साथ ये कॉफी,कविता, विश्वास कहां से आ गये? और यह हैं कौन? जिसके दम पर तुम मुझे ललकार रहे हो।जल्दी बोल वरना तेरी खैर नहीं, मैं प्रक्रिया हूं और रचना मेरी बदौलत है। इन तीनों के चक्कर में पड़े तो कहीं के नहीं रहोगे।

यह सुनकर कवि को झटका लगा। उसने बुद्धिजीवी वाला चोला उतारा और आम आदमी बनकर कविता की तलाश में कॉफी हाउस से निकलकर सड़क पर टहलने लगा।

विश्व दाल दिवस

प्रमोद दीक्षित मलय

लेखक शिक्षक एवं शैक्षिक संवाद मंच के संस्थापक हैं।

घर-आंगन में बिखरती रहे दाल की खुशबू

पाठक सोच रहे होंगे कि दाल विषयक लेख के आरम्भ में उपर्युक्त प्रसंग मैंने क्यों लिखा। दरअसल मैं बताना चाह रहा हूं कि दाल के बिना हमारा भोजन बेस्वाद, नीरस और अपूर्ण है। दाल ही है जो भोजन की थाली के सौंदर्य, स्वाद, संतुष्टि और पोषण-संतुलन को संभालती एवं वृद्धि करती है। दाल के बिना स्वस्थ शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि दालें मानव शरीर के लिए अत्यावश्यक प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत एवं संसाधन हैं, साथ ही फाइबर, खनिज एवं विटामिन का भी। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के लिए प्रति किलोग्राम वजन हेतु 0.8 से 1.7 ग्राम प्रोटीन की जरूरत प्रतिदिन पड़ती है। मोटे तौर पर कहें तो न्यूनतम 50-60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक है। प्रोटीन न केवल शरीर के विकास के लिए एक जरूरी तत्व है बल्कि वह देह के अंदरूनी अंगों की मरम्मत का काम भी करता है। एंजाइम एवं हार्मोन के उत्पादन में सहयोग, मांसपेशियों, त्वचा, हड्डी, बाल, नाखून आदि के साथ शरीर के ऊतकों का निर्माण करता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सबल करता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाने पर ऊर्जा की आपूर्ति एवं पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक है। इतना ही नहीं, शरीर के पीएच मान के संतुलन को भी बनाये रखता है। कह सकते हैं कि प्रोटीन मानव शरीर का सुपर हीरो हैं और दालें सुपर फूड।

यही कोई दस साल पहले की बात होगी। मुझे सह-समन्वयक (हिंदी भाषा) के पद पर काम करते हुए तीन साल हो चुके थे। प्राथमिक शिक्षा की बेहतरी के लिए मन में बहुत उत्साह था। लगभग प्रतिदिन ही किसी न किसी विद्यालय में जाना होता था। बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों, प्रबंध समिति के सदस्यों और गांव के आम निवासियों से विद्यालय विकास की बातचीत करता, सहयोग हेतु प्रेरित करता। परिणाम भी आने लगे थे, एक अच्छा शैक्षिक माहौल बन गया था। ये सब करते हुए कुछ ग्रामवासियों से स्नेह, मधुरता एवं आत्मीयता के स्वाभाविक सम्बन्ध भी विकसित हुए और शादी-विवाह एवं जन्म-मरण के अवसरों पर मेरी उपस्थिति होने लगी थी। सामाजिक रिश्ते की यह डोर भावना के रस से भींगी हुई थी। एक दिन शाम को एक गांव से फोन आया, 'सर! कल आप स्कूल आ रहे हैं न। आपका भोजन हमारे साथ होगा। दाल, बाटी, चोखा, रायता रहेगा सर।' वह गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और एक ही सांस में पूरी बात कह गये। मुझे हां कहना ही था। वह विद्यालय एक मजरे में आबादी के बाहर एक बगीचे के निकट स्थित प्राथमिक स्कूल था। वह बुजुर्ग व्यक्ति उसी बगीचे में सपरिवार रहते थे। विद्यालय के सहयोग हेतु सदैव तत्पर, वह एक संवेदनशील सहयोगी व्यक्ति थे।

मैं जब विद्यालय पहुंचा तो वह वहीं उपस्थित थे। विद्यालय का संक्षिप्त कार्यक्रम पूरा कर अन्य शिक्षकों के साथ हम लोग बाग पहुंचे। वहां दो-तीन लोग भोजन की तैयारी में जुटे थे। उपलों की आग पर भुन रहे आलू-बैंगन की सोंधी महक ने मन मोह लिया। ईटों के चूल्हे पर मिट्टी के घड़े में मिक्स दाल (अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर) खदबदा रही थी, और एक आदमी करछुल से दाल का छाग बाहर करता जा रहा था। दाल पकने के बाद उसमें लाल साबुत मिर्च, जीरा, हींग, तेजपत्ता, डोंडा एवं लौंग को सरसों के तेल में तड़का कर छौंका लगाया गया, तो खुशबू पूरे बगीचे में फैल गयी और स्वाद मुंह में उतर आया। प्रेम पूर्वक भोजन कर हम विदा हुए।

पाठक सोच रहे होंगे कि दाल विषयक लेख के आरम्भ में उपर्युक्त प्रसंग मैंने क्यों लिखा। दरअसल मैं बताना चाह रहा हूं कि दाल के बिना हमारा भोजन बेस्वाद, नीरस और अपूर्ण है। दाल ही है जो भोजन की

थाली के सौंदर्य, स्वाद, संतुष्टि और पोषण-संतुलन को संभालती एवं वृद्धि करती है। दाल के बिना स्वस्थ शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि दालें मानव शरीर के लिए अत्यावश्यक प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत एवं संसाधन हैं, साथ ही फाइबर, खनिज एवं विटामिन का भी। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के लिए प्रति किलोग्राम वजन हेतु 0.8 से 1.7 ग्राम प्रोटीन की जरूरत प्रतिदिन पड़ती है। मोटे तौर पर कहें तो न्यूनतम 50-60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक है। प्रोटीन न केवल शरीर के विकास के लिए एक जरूरी तत्व है बल्कि वह देह के अंदरूनी अंगों की मरम्मत का काम भी करता है। एंजाइम एवं हार्मोन के उत्पादन में सहयोग, मांसपेशियों, त्वचा, हड्डी, बाल, नाखून आदि के साथ शरीर के ऊतकों का निर्माण करता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सबल करता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाने पर ऊर्जा की आपूर्ति एवं पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक है। इतना ही नहीं, शरीर के पीएच मान के संतुलन को भी बनाये रखता है। कह सकते हैं कि प्रोटीन मानव शरीर का सुपर हीरो हैं और दालें सुपर फूड। इसीलिए दालों के महत्व से परिचित कराने, टिकाऊ खेती में दालों की भूमिका के बारे में जागरूकता का प्रसार करने तथा मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारने में दालों के योगदान से जन सामान्य को रू-ब-रू कराने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा प्रतिवर्ष 10 फरवरी को जागतिक आयोजन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि खाद्य एवं खाद्य संगठन ने वर्ष 2016 में अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष मनाया था, और एक नारा दिया था - स्वस्थ आहार और ग्रह के लिए दलहन से प्यार करें। उस आयोजन से प्राप्त निष्कर्ष, प्रेरणा एवं ऊर्जा से खाद्य एवं कृषि संगठन की पहल पर दिसम्बर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस के रूप में मनाते हुए मानव शरीर, मिट्टी एवं पर्यावरण में दालों की योगदान से परिचित कराने हेतु घोषित किया था। तब पहला आयोजन 10 फरवरी, 2019 को किया गया। प्रत्येक वर्ष आयोजनों हेतु एक थीम निर्धारित की जाती है। वर्ष 2026 की थीम है- विश्व की दलहन : सादगी से उत्कृष्टता की ओर, जबकि वर्ष 2025 की थीम थी- दलहन : कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। थीम से आयोजनों को दिशा मिलती है और प्रेरणा भी।

भारत दालों के उत्पादन में अग्रणी है। विश्व के कुल दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा 25-30 प्रतिशत है। गतवर्ष भारत में 28 मीट्रिक टन दालों का उत्पादन हुआ। दाल उत्पादन में सिरमौर होने के बावजूद भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल आयातक देश भी है, क्योंकि दाल के उपभोग में भी सर्वोपरि है। भारत में सर्वाधिक दाल उत्पादन के राज्य मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्रप्रदेश हैं। जबकि विश्व में भारत के बाद कनाडा, म्यांमार, चीन, आस्ट्रेलिया और रूस प्रमुख दाल उत्पादक देश हैं। विश्व के लगभग 170 देश कुल 9.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि में विभिन्न प्रकार की दालें उगाते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन ने चना, मसूर, अरहर, मूंग, उड़द, मटर, लोबिया, सेम प्रजाति की फलियों सहित 11 प्रकार की दालों को मान्यता दी है। चना को दालों का राजा तो मूंग को दालों की रानी कहा जाता है। भारत में कुल दाल उत्पादन में 40 प्रतिशत हिस्सा चना दाल का है। चना दाल का उपयोग भोजन के अलावा मिठाई, बेसन और नमकीन बनाने में किया जाता है। शादी-विवाह, तिथि-त्योहारों एवं शुभ अवसरों पर चने की दाल रांधने की परम्परा है। रोगियों के पथ्य के रूप में मूंग की दाल और उससे बनी खिचड़ी दी जाती है तथा मूंग की दाल का हलुवा और पराठे का स्वाद जीभ पर सालों बस रहता है तथा अदरक, मिर्च, धनिया पत्ती, लहसुन की टमाटर वाली चटनी के साथ जाड़ों में मुंगौड़े खाने का अलौकिक आनंद है। उड़द की दाल शक्तिवर्धक होती है, किंतु गरिष्ठ और बादी भी। लेकिन कुरकुरी-करारी स्वादिष्ट कचौड़ियां तो उड़द की दाल की ही बनती हैं और बड़े-भल्ले भी, और तब छुहारे, इमली, गुड़ की चटनी के साथ खाने वालों का पेट भर सकता है मन नहीं। अरहर की दाल दैनंदिन भोजन की थाली की शोभा है। इन दालों का अपना गुण-धर्म होता है, शरीर के लिए सुपाच्य, स्वादिष्ट एवं पोषक बनाने हेतु तड़का लगाना आवश्यक होता है जो हर दाल के लिए अलग-अलग होता है। अरहर की दाल में जीरा, मूंग में डोंडा और लौंग, उड़द में हींग और अदरक, मसूर में हींग और राई तथा चना में हींग का छौंक लगाने से स्वाद और सुगंध में वृद्धि होती है। प्याज, लहसुन, करी पत्ता, तेजपत्ता, साबुत लाल मिर्च, दही, टमाटर आदि डालकर अलग प्रकार से छौंक भी लगा सकते हैं। कल्पना से दालों के विभिन्न व्यंजन आज परोसे जा रहे हैं। मानव शरीर के लिए उपयोगी दाल की सुगंध हमारे घर-आंगन में बसी रहे, दालों का स्वाद मुंह में घुलता रहे, यही कामना है।

कछुओं की तस्करी

डॉ. तेज प्रकाश पूर्णानन्द व्यास

लेखक प्रकृति और वन्य जीव वैज्ञानिक हैं।

पर्यावरण सुरक्षा चक्र पर एक प्राणघातक प्रहार

मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन पर उस समय स्तब्ध कर देने वाला दृश्य उपस्थित हुआ, जब पटना-इंदौर एक्सप्रेस (19314) के भीतर से प्रकृति के 311 मूक रक्षकों मीठे पानी कछुओं को बंधक अवस्था में मुक्त कराया गया। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने अपने गुप्तचर तंत्र और सतर्कता का परिचय देते हुए न केवल इन जीवों को बचाया, बल्कि वन्यजीव तस्करी के उस घृणित तंत्र की जड़ों को भी बेनकाब किया है जो लखनऊ से लेकर इंदौर तक फैला हुआ है।

अधिकारियों की सजग दृष्टि ने जब ट्रेन के वातानुकूलित कोच के परिचारक (अटेंडेंट) अजय राजपूत के व्यवहार में घबराहट देखी, तो संदेह की सुई गहरी हो गई। आरक्षित केबिन की गहन तलाशी में दो भारी बैग बरामद हुए, जिनमें निर्दयतापूर्वक, बिना वायु के संचार के, 311 जीवित कछुओं को ठूंस-ठूंस कर भरा गया था। पूछताछ के दौरान अपराधी ने स्वीकार किया कि लखनऊ स्थित रवींद्र कश्यप नामक व्यक्ति ने उसे मात्र 2500 रुपये के तुच्छ लालच में इस महापाप का भागीदार बनाया। ये कछुए देवास और इंदौर के बाजारों में 'एक्वेरियम पेट्स' के रूप में ऊंचे दामों पर बेचे जाने थे, जहाँ इनकी कीमत लाखों में आंकी गई है। यह घटना स्पष्ट करती है कि किस प्रकार वन्यजीवों का यह काला बाजार हमारी जैव-विविधता को निगल रहा है।

प्रजाति पहचान और जैव-भौतिकी :

चित्र में दिखाई देने वाले अधिकांश कछुए 'इंडियन रूफ्ड टर्टल' (Pangshura tecta) और 'इंडियन टेंट टर्टल' (Pangshura tentoria) की श्रेणी के हैं। इनके कवच (Carapace) की बनावट एक ढालनुमा छत की तरह होती है, जिस पर एक उभारदार 'कील' (Keel) मौजूद होती है। इन प्रजातियों के कछुओं को उनके सुंदर और चमकीले पेट (Plastron) के लिए जाना जाता है, जिस पर नारंगी, गुलाबी और काले धब्बे होते हैं। यही सुंदरता इनके लिए अभिशाप बन गई है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग 'शो-पीस' के रूप में अत्यधिक है। इनका जीवन चक्र अत्यंत धीमा होता है; इन्हें वयस्क होने में कई वर्ष लगते हैं। जब तस्कर इतनी बड़ी संख्या में किशोर (Juveniles) कछुओं को नदी से उठा लेते हैं, तो वे उस प्रजाति के भविष्य की प्रजनन क्षमता को ही समाप्त कर देते हैं।

लखनऊ और गोमती नदी का पारिस्थितिकीय महत्व: इस तस्करी का मुख्य केंद्र लखनऊ बताया गया है। लखनऊ की जीवनरेखा, गोमती नदी और उससे जुड़े तराई के जल निकाय इन कछुओं के लिए स्वर्ग समान रहे हैं। वैज्ञानिक रूप से, कछुए नदी के 'वैक्यूम क्लीनर' होते हैं। ये मरे हुए जलीय जीवों, सड़ी-गली वनस्पतियों और हानिकारक बैक्टीरिया को खाकर जल को शुद्ध रखते हैं। लखनऊ जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहाँ नदियों पर प्रदूषण का अत्यधिक दबाव है, ये कछुए प्राकृतिक 'वाटर प्यूरीफायर' का कार्य करते हैं। यदि इन कछुओं को गोमती या सरयू के जल निकायों से इसी प्रकार निकाला जाता रहा, तो इन नदियों की स्व-शुद्धिकरण (Self-purification) की क्षमता शून्य हो जाएगी। कछुओं की अनुपस्थिति में जल में अमोनिया और नाइट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मछलियाँ मरने लगती हैं और अंततः वह जल मानव उपयोग के योग्य भी नहीं रहता।

पारिस्थितिकीय 'इकोसाइड' : बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी और वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के शोध और मेरे शोध अनुसार , मीठे पानी के कछुए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के 'कीस्टोन' हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि इस जीव को हटा दिया जाए, तो पूरा तंत्र ढह जाएगा।

311 कछुओं का अपहरण केवल एक संख्या नहीं है। प्रत्येक कछुआ प्रतिदिन सैकड़ों ग्राम जैविक अपशिष्ट का निपटान करता है। जब इन्हें लखनऊ से हटाकर इंदौर के कंक्रीट के जंगलों में कांच के डिब्बों (Aquariums) में कैद करने के लिए भेजा जाता है, तो हम एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र की हत्या कर रहे होते हैं। यह प्रकृति के विरुद्ध 'संगठित युद्ध' है। तस्करों द्वारा इन्हें बोरों में बांधकर ले जाना इनके श्वसन तंत्र और सेल (Shell) को अपूरणीय क्षति पहुँचाता है। कई कछुए परिवहन के दौरान ही दम तोड़ देते हैं, जो एक वैज्ञानिक के रूप में हमारे लिए असहनीय क्षति है।

अधिनियम और कठोर दंडः भारतीय कानून वन्यजीवों के संरक्षण हेतु विश्व के सबसे कठोर कानूनों में से एक है। इन कछुओं की तस्करी करने वालों पर निम्नलिखित कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित हैः वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचीः चित्र में दिख रहे 'स्पॉटेड पोंड टर्टल' या 'इंडियन रूफ्ड टर्टल' को इस अधिनियम की अनुसूची-1 (Schedule I) में रखा गया है। इसका अर्थ है कि इन्हें वही कानूनी संरक्षण प्राप्त है जो एक बाघ या हाथी को मिलता है। धारा 9 और धारा 39ः वन्यजीवों के शिकार और उनके अवैध कब्जे को प्रतिबंधित करती है। चूंकि ये सरकारी संपत्ति (State Property) माने जाते हैं, अतः इनका परिवहन देश के विरुद्ध अपराध है, याने राष्ट्रे अपराध की श्रेणी में आते हैं।

दंड का प्रावधान (Section 51): अनुसूची-1 के जीवों के साथ छेड़छाड़ या तस्करी करने पर अपराधी को न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के कठोर कारावास का प्रावधान है। साथ ही, न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। यदि यह अपराध दूसरी बार किया जाता है, तो कारावास की अवधि और जुर्माने की राशि दोनों में भारी वृद्धि होती है। गैर-जमानती अपराधः यह एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें अपराधी को तत्काल राहत मिलना असंभव होता है। IUCN संरक्षण स्थिति और वैश्विक चिंता अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की 'रेड लिस्ट' में इन प्रजातियों की स्थिति चिंताजनक है। 'स्पॉटेड पोंड टर्टल' (Geoclemys hamiltonii) को 'Endangered' (लुप्तप्राय) घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया, तो ये पृथ्वी से हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। साइट्स (CITES) के अपेंडिक्स-I में शामिल होने के कारण इनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी पूर्णतः प्रतिबंधित है।

तस्करी की ये घटनाएँ भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि यह जैव-विविधता की चोरी है। एक हरपेटोलॉजिस्ट के रूप में, मेरा हृदय उन 311 मूक प्राणियों की पीड़ा को महसूस कर सकता है। जिस जीव को करोड़ों वर्षों के उद्विकास (Evolution) ने नदियों को स्वच्छ रखने के लिए बनाया, उसे आज चंद रुपयों के लिए प्लास्टिक के थैलों में घोंटा जा रहा है। लखनऊ के जल निकायों से इन कछुओं का निष्कर्षण उस क्षेत्र के जल सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। प्रशासन को मुख्य सरगना 'रवींद्र कश्यप' जैसे लोगों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा द्य नदियाँ मरेंगी, तो सभ्यताएं मरेंगी। और नदियों को जीवित रखने का कार्य ये कछुए निःशुल्क कर रहे हैं। इन मुक्त कराए गए कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें इनके स्वास्थ्य की जांच और 'क्वारंटीन' अनिवार्य है, ताकि किसी भी बाहरी संक्रमण से प्राकृतिक जल निकाय सुरक्षित रहें।

सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर विशेष

योगेश कुमार गोयल

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

इंटरनेट को वरदान बनाएं, अभिशाप नहीं

इंटरनेट आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, जिसने हमारा जीवन तो आसान बनाया ही है, वहीं कोरोना काल के बाद से इंटरनेट की महत्ता कई गुना बढ़ गई है। डेटा और सांख्यिकी से जुड़ी जानकारी देने वाली इंटरनेट साइट 'स्टेटिस्टा' के मुताबिक, भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार है। वैश्विक महामारी के दौरान भारत में केवल दो वर्षों में ही डिजिटल लेन-देन में करीब 51 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली थी, जिसके बाद से यह लगातार बढ़ रही है। मनोरंजन, संचार, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन लेन-देन, खरीदारी तथा अन्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाना एक इंटरनेट उपयोगकर्ता की आम गतिविधियों में शामिल हो गया है। ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग तथा टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकों में इस्तेमाल होता इंटरनेट अब घर-घर की जरूरत बन गया है, लेकिन इसके साथ ही असुरक्षित इंटरनेट के खतरे भी कई गुना बढ़ गए हैं।

भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है लेकिन अधिकांश लोगों को सुरक्षित इंटरनेट के उपयोग के बारे में जानकारी नहीं है। इसी कारण इंटरनेट के जरिये वित्तीय अपराधों के अलावा भी कई तरह के साइबर अपराधों का सिलसिला शुरू हो गया है। यूनिसेफ के अनुसार, दिसंबर 2017 में भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या करीब 48.1 करोड़ थी, जिनमें से 60 प्रतिशत छात्र और युवा थे। भारत के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ अब ग्रामीण क्षेत्र भी 'डिजिटल इंडिया' मुहिम के तहत आगे बढ़ रहे हैं और ग्रामीण आबादी भी भारत में इंटरनेट के विकास को नई गति दे रही है। 'इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (आईएएमएआई) और 'कांतार' की रिपोर्ट 'इंटरनेट इन इंडिया' के मुताबिक, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2024 में 88.6 करोड़ तक पहुंच गई थी और 2025 के दौरान यह 95.8 करोड़ पहुंच गई। 2020 में यह संख्या 74.9 करोड़ थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ता शहरी क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं। 2024 में भारत में कुल सक्रिय 88.6 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से 48.8 करोड़ ग्रामीण इलाकों से थे, जो देश के कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का 55 प्रतिशत हिस्सा है।

देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से 47 प्रतिशत महिलाएं हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल क्रांति अब केवल भारत के शहरों तक ही सीमित नहीं है बल्कि गांवों तक भी अपनी पहुंच बना रही है और वह भी हर वर्ग में। इंटरनेट का यह विस्तार 'डिजिटल इंडिया' के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंटरनेट उपयोगकर्ता प्रतिदिन औसतन 90 मिनट इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें शहरी उपयोगकर्ता थोड़ा ज्यादा समय (94 मिनट) तक इंटरनेट चलाते हैं जबकि 89 मिनट के साथ ग्रामीण उपयोगकर्ता उनसे थोड़ा पीछे हैं। हालांकि, देश की 41 प्रतिशत आबादी अभी भी इंटरनेट उपयोग नहीं करती, जिसके प्रमुख कारणों में इंटरनेट से जुड़ी जागरूकता की कमी, इंटरनेट एक्सेस प्वाइंट का उपलब्ध न होना और तकनीकी जानकारी की कमी शामिल हैं। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं के उपयोगकर्ताओं की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। वर्ष 2011 में भारतीय भाषाओं के 4.2 करोड़ उपयोगकर्ता थे, जो 2016 में बढ़कर 23 करोड़ से भी ज्यादा हो गए और कोरोना काल में यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। सस्ते डेटा पैक के कारण एक ओर जहां इंटरनेट तक लोगों की आसान पहुंच के चलते शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, वहीं इंटरनेट लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला रहा है।

दूसरी ओर, इंटरनेट की हर किसी तक आसान पहुंच होने के कारण साइबर बुलिंग (ऑनलाइन दमनकारी व्यवहार अथवा बदसलूकी), फिशिंग तथा निजी जानकारियों के सार्वजनिक होने के खतरों के अलावा और भी कई प्रकार की समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। देश में आधे से अधिक ऑनलाइन खरीदार सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सामान खरीदते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 500 मिलियन से अधिक डिजिटल लेन-देन होते हैं। करीब 98 प्रतिशत इंटरनेट उपयोगकर्ता स्थानीय भाषाओं में कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं। शहरों में हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, तेलुगु और बंगाली भाषा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, साथ ही खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में वॉयस कमांड का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि, सुरक्षित इंटरनेट के उपयोग को लेकर अपेक्षित जानकारियों के अभाव में लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यूनिसेफ के अनुसार, बुलिंग और साइबर बुलिंग एक-दूसरे को बढ़ावा देते हैं और इससे दुर्व्यवहार का चक्र लगातार चलता रहता है। साइबर बुलिंग से पीड़ित व्यक्ति जीवनभर इसकी क्षति से पीछा नहीं छुड़ा पाते। गंभीर स्थितियों में साइबर बुलिंग की वजह से आत्महत्याएं भी हुई हैं।

इंटरनेट से जुड़े खतरों की बढ़ती चुनौतियों के कारण ही अब इंटरनेट को सुरक्षित बनाने पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। खासकर बच्चों तथा युवाओं को ऑनलाइन तथा मोबाइल फोन के सुरक्षित व ज्यादा जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष फरवरी माह के दूसरे मंगलवार को 'सुरक्षित इंटरनेट दिवस' मनाया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2026 का विषय है 'स्मार्ट तकनीक, सुरक्षित विकल्प : एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग की खोज'। यह दिवस पहली बार 6 फरवरी 2004 को यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित 'सेफ बॉर्डर्स' परियोजना के भाग के रूप में मनाया गया था। यह अब 190 से भी ज्यादा देशों में मनाया जाता है। 'सुरक्षित इंटरनेट दिवस' के अवसर पर इंटरनेट सुरक्षा के उपायों का उल्लेख करना आवश्यक है। इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए कुछ जरूरी उपाय अपनाकर असुरक्षित इंटरनेट से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से बचा जा सकता है। अपने मोबाइल या कम्प्यूटर पर सदैव मजबूत पासवर्ड चुनें और अपने अकाउंट को बेहतर करने के लिए गूगल सिक्योरिटी चेक करें। अकाउंट को अतिरिक्त रूप से सुरक्षित रखने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। किसी भी वेबसाइट पर जाते समय उसके यूआरएल पर ध्यान दें और जालसाजी वाले संदेशों से सावधान रहें। फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके और उन्हें अपडेट करके साइबर हमलों से बच सकते हैं। सार्वजनिक इंटरनेट नेटवर्क का उपयोग करते समय संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचें। अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और किसी भी अनजान व्यक्ति से अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

कुल मिलाकर, इंटरनेट आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है लेकिन इसके सुरक्षित उपयोग की जानकारी और सतर्कता भी उतनी ही आवश्यक है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस जैसे प्रयासों से लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सकता है, जिससे वे ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से सुरक्षित रह सकें। हमें चाहिए कि हम सभी इंटरनेट को जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ उपयोग करें ताकि यह हमारे लिए एक सुरक्षित और उपयोगी साधन बना रहे।

प्रवासी आयोग बना, कामकाज का हिसाब नहीं

भोपाल में मंत्री प्रहलाद पटेल बोले-3 साल आयोग रहा, कुछ तो बता दो, एक भी पन्ना नहीं है

भोपाल। राज्य में प्रवासियों मजदूरों के लिए एक्ट भी था और आयोग भी था लेकिन तीन साल तक रहे इस आयोग की कोई रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। इसके लिए बने पोर्टल पर किसी पंचायत के प्रवासी मजदूर का नाम नहीं है। नाम तो कहीं नहीं लिखे लेकिन संख्या जरूर लिखी है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने ये बातें रविवार को कहीं। वे भोपाल में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला सूचना शिक्षा और संचार के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंत्री पटेल ने कहा कि प्रवासी आयोग की रिपोर्ट में एक भी पन्ना नहीं है, दो लाइनें नहीं लिखी हैं। मैंने मंत्री बनने के बाद पूछा कि 3 साल आयोग रहा, कुछ तो बता दो। जिस पर मैं कुछ कह सकूं। आयोग के कामकाज का कोई हिसाब किताब कुछ नहीं है। कम से कम नाम पता तो हो कि कहां गए थे लेकिन कुछ भी नहीं है। पटेल ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की बड़ी चुनौतियां हैं। यह आश्चर्य की बात है कि इसको लेकर राज्य सरकार के पंचायत विभाग में सर्कुलर भी जारी किया था लेकिन काम नहीं हुआ। पंचायत से अगर कोई बाहर जा रहा है तो सिर्फ वही बस प्रवासी नहीं है बल्कि कोई बाहर से आकर हमारे यहां श्रम कर रहा है तो वह भी प्रवासी ही है। जनपद सीईओ से आग्रह है कि इसको लेकर काम करें। लोगों के माइग्रेट करने पर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है क्योंकि वह भी साथ जाते हैं इसके बारे में हमें सोचना होगा।

मजदूरों के बच्चों की जिम्मेदारी हमारी

मंत्री पटेल ने कहा कि यह कहा जाता है कि हमारे राज्य में बंधुआ मजदूर नहीं है लेकिन कुछ स्थानों पर मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने की शिकायत आई है। यह ठीक नहीं है, बाल श्रमिकों के मामले में हम इतनी गंभीर नहीं है यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमने डेटा कलेक्शन कराया है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो 12वीं के बाद फाइनेंशियल लिंकेज की स्थिति में नहीं है और उनके माता-पिता उनके जन्म के समय से ही उनके पास नहीं है तो उसकी रिपोर्ट कीजिए। हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं जब तक ऐसे बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो जाए तब तक उन्हें हम झेलेंगे।

सीईओ की कम मौजूदगी पर जताई नाराजगी

कार्यशाला के समापन कार्यक्रम में मंत्री पटेल ने जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की कार्यशाला में कम मौजूदगी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वे लिखित में इसका कारण लेंगे कि आखिर क्यों नहीं आए? कलेक्टर ने नहीं आने दिया तो उसका लिखित जवाब देना होगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बैठक में नहीं आए तो बताना होगा। मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार की ओर से पंचायत के विकास के लिए दिया जाने वाला पैसा सीधे ग्राम सभा के खाते में पहुंचना चाहिए। जनपद सीईओ को इस बात का विकल्प देखना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि सीधे ग्राम सभा के खाते में रकम जाए और उसका भुगतान संबंधित व्यक्ति को हो जाए। स्टाम्प ड्यूटी, मनरेगा, वित्त आयोग का पैसा ग्राम पंचायत को जाता है तो हमारी चुनौती यह है कि यदि रोजगार करना चाहते तो फंड कहां से आएगा। राज्यपाल की बैठक में भी यह मुद्दा उठ चुका है। मंत्री पटेल ने कहा कि संचालक पंचायत ने ग्राम सभाओं के खातों को एक्टिवेट करने के लिए रू. 1 डालकर यह चेक किया है कि खाता एक्टिवेट है या नहीं। मंत्री पटेल ने कहा कि सरपंच के खाते से ग्राम सभा के खाते में पैसा पहुंचाने के मेकैनिज्म के बारे में सोचना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मोबिलाइजर की जिम्मेदारी है कि वह हर महीने गांव में जाएं और बैठक लें, अगर ऐसा नहीं करते तो उनके काम पर भी सवाल उठते हैं। पेसा पंचायत में एक माह में ग्राम सभा होना जरूरी है, इसको लेकर जल्दी ही निर्देश जारी जारी किए जाएंगे।

अमलतास इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी में महिला स्वास्थ्य एवं कैंसर स्क्रीनिंग पर जागरूकता सेमिनार संपन्न

देवास। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी में महिला स्वास्थ्य एवं कैंसर स्क्रीनिंग विषय पर एक जागरूकता सेमिनार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संस्थान के फैकल्टी सदस्यों की उल्लेखनीय सहभागिता रही।

सेमिनार की मुख्य वक्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रितु शारदा (गायनेकोलॉजिस्ट) रहीं। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य, स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर की प्रारंभिक पहचान, समय पर जांच एवं नियमित स्क्रीनिंग के महत्व पर

विस्तार से प्रकाश डाला। संस्थान के चेयरमैन श्री मयंक राज सिंह भदौरिया ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता समाज की प्राथमिक आवश्यकता है। वहीं प्राचार्य डॉ. योगेन्द्र सिंह भदौरिया ने अपने उद्बोधन में ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रमों को विद्यार्थियों एवं फैकल्टी के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। सेमिनार का सफल आयोजन डॉ. शहला जाफरी, डॉ. अंकित शर्मा एवं डॉ. विभा पाटणकर के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का संचालन (एंकरिंग) छात्रा इंशिरा खान एवं छात्र हितेश राय द्वारा प्रभावी रूप से किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित हुआ, जिसमें उपस्थित फैकल्टी सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता की। आयोजकों ने भविष्य में भी इस प्रकार के जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

आज होगा सैन जी महाराज की छतरी का अनावरण

देवास। सिविल लाइन रोड स्थित तिराहे पर सैन जी महाराज की छतरी का अधिकृत रूप से होगा अनवारण। तिराहे का सौंदर्यीकरण, लगा हाईमास्ट, विकसित गार्डन से छतरी होगी सुशोभित। 25 लाख की लागत से सिविल लाइन स्थित तिराहे पर विराजित सैन जी महाराज की छतरी का देवास विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार के मुख्य आतिथ्य में मंगलवार 10 फरवरी को दोपहर 2 बजे सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, महापौर श्रीमती गीता अग्रवाल, सभापति रवि जैन, जिलाध्यक्ष रायसिहं सेंधव, विधायक एवं महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, आयुक्त दलीप कुमार के विशेष आतिथ्य में होगा अनावरण।

नेता सत्तापक्ष मनीष सेन ने बताया कि वार्ड 25 में राशि 25 लाख की लागत से निगम ने विकसित किया तिराहा। सिविल लाईन तिराहे पर स्थित सैन जी महाराज की छत्री के निर्माण के साथ विकसीत गार्डन ओर हाईमास्ट का कार्य सम्पन्न हुआ। आज मंगलवार 10 फरवरी को विधायक श्रीमंत पवार अतिथियों के साथ करेंगे छत्री का अनावरण।

उत्कृष्ट व मॉडल स्कूलों की प्रवेश परीक्षा में 307 विद्यार्थी रहे अनुपस्थित

बैतूल। जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूल एवं श्रमोदय विद्यालय की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के लिए जिले भर में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसमें बैतूल जिला मुख्यालय पर 12 केंद्रों एवं ब्लॉक मुख्यालयों मुलताई, भैंसदेही, आमला, चिचोली, शाहपुर और घोड़ाडोंगरी में परीक्षा आयोजित की। इस परीक्षा में कुल 4296 विद्यार्थियों को शामिल होना था, लेकिन इनमें से 307 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। श्रमोदय विद्यालय के लिए 35 विद्यार्थियों को शामिल होना था, लेकिन इनमें से 7 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा का आयोजन सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक किया गया। संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्कृष्ट विद्यालय बैतूल में कक्षा 9वीं तथा जिले के तीन मॉडल स्कूलों घोड़ाडोंगरी, शाहपुर और भीमपुर में प्रवेश के लिए आयोजित की थी। उत्कृष्ट विद्यालय बैतूल में कक्षा 9वीं के लिए कुल 240 सीटें निर्धारित हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

30 एकड़ का मालिक पिता दर-दर भटक रहा

बुजुर्ग पिता को न्याय दिलाने एसपी ऑफिस पहुंचे बालाजीपुरम संस्थापक सेम वर्मा

बैतूल। 30 एकड़ जमीन का मालिक और पांच लडक़ों के पिता ने कभी नहीं सोचा था कि उसे बुढ़ापे में दाने-दाने को मोहताज होना पड़ेगा और उसकी ही संतानें उसकी जान की दुश्मन बन जाएंगी, लेकिन ऐसा ही कुछ देखना पड़ रहा है। बैतूल जिले के आमला के ससुंद्रा गांव के भद्दू धाकड़ को, आज सोमवार की सुबह बालाजीपुरम संस्थापक सेम वर्मा इस बुजुर्ग को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे और दोषी बच्चों के खिलाफ कार्रवाई और जमीन से बेदखल कर वापस जमीन पिता को दिलाने की मांग की। एसपी ने भी तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। इस दौरान बुजुर्ग भद्दू ने सभी को अपनी प्रताडऩा की दर्दभरी कहानी सुनाई। एक समय ससुन्द्रा गांव के पटेल कहलाने वाले भद्दू जब बुजुर्ग हुए तो बेटों ने खेती संभाली। लेकिन यहीं से उनकी दुर्दशा आरंभ हुई। शादी होने के बाद बच्चों ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अपनी कहानी बताते हुए बुजुर्ग भद्दू की आंखों में गुस्सा और आंसू एक साथ आते हैं। वे बताते हैं कि बच्चों ने विशेषकर दोनों बड़े लडक़ों ने उन्हें बहुत मारा और जान से मारने की कोशिश की। कई कई दिन तक वे कमरे में बंद रखते थे। उनकी पत्नी को भी प्रताड़ित करते हैं अब वह लकवे का शिकार है। इस पूरे मामले की शिकायत उन्होने आमला थाने से लेकर, कलेक्टर-एसपी और मुख्यमंत्री तक की। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम आमला ने जरूर एक-एक हजार रूपये प्रति माह भरण-पोषण देने का आदेश पांचों बच्चों को दिया। लेकिन किसी ने कभी कोई पैसा नहीं दिया। एसडीएम ने थाना प्रभारी को कार्रवाई के लिए लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव बैतूल आए थे, तब बुजुर्ग परेशान होकर आत्मदाह के लिए पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।

बालाजीपुरम् देगा बुजुर्ग का साथ – बालाजीपुरम संस्थापक सेम वर्मा सोमवार को बुजुर्ग को साथ लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सुनील व्दिवेदी, बलवंत धोटे, बबलू खुराना, अशोक देशमुख, राज बाघमारा आदि थे। लंबे समय से बुजुर्ग की निशुल्क सहायता करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक पाल और श्रेयांस पाल भी थे। श्री वर्मा ने बताया कि बुजुर्ग बालाजी के दरबार अपनी अर्जी लेकर आया था। वृंदावन से फूलवती माता की घर वापसी से वह प्रभावित था। इसलिए बालाजीपुरम परिवार उसको हर हाल में न्याय दिलाएगा। एसपी वीरेंद्र जैन ने थाना प्रभारी आमला को दोषी लडक़ों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावे-आपत्ति एवं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी निराकरण में बैतूल जिला प्रथम

विशेष गहन पुनरीक्षण में बैतूल अव्वल, शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल

बैतूल। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दावे-आपत्तियों के निराकरण एवं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के समाधान में बैतूल जिले ने शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिले के सभी बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, बीएलओ सहयोगी रोजगार सहायक आदि द्वारा समन्वित एवं प्रतिबद्ध रूप से कार्य किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जिले ने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। जिले के समस्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने भी इस कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कुल मतदाता संख्या 11 लाख 95 हजार 558 है। नोमैपिंग एवं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कुल 1 लाख 72 हजार 027 प्रकरण चिन्हित किए गए, जिनमें सभी प्रकरणों की सुनवाई पूर्ण कर निराकरण किया गया। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और नो मैप मतदाताओं को छोड़कर 8 लाख 90 हजार 548 मतदाता त्रुटिरहित पाए गए, जो अंतिम मतदाता सूची के लिए पार्क किए गए। पूर्व में बीएलओ पत्र के माध्यम से 1 लाख 32 हजार 653 मतदाताओं की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का निराकरण करा लिया गया था तथा बाद में 1 लाख 71 हजार 828 मतदाताओं को सूचना पत्र जारी कर जानकारी एवं दस्तावेज प्राप्त कर उनकी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का निराकरण किया गया। नो मैपिंग अंतर्गत 213 मतदाता तथा अन्यत्र शिफ्ट हो जाने या मृत होने से 316 मतदाता अपात्र पाए गए। इस प्रकार 11 लाख 95 हजार 558 में से मात्र 529 मतदाताओं को छोड़कर शेष सभी 11 लाख 95 हजार 029 मतदाता अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलित होंगे।

अवैध खनिज परिवहन पर कार्यवाही

खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन करते एक डम्पर जप्त

बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशों के पालन में खनिज विभाग द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण एवं सतत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में 9 फरवरी को खनि निरीक्षक बैतूल द्वारा तहसील बैतूल अंतर्गत ग्राम उड़दन-साकादेही के समीप खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए डम्पर वाहन क्रमांक एमपी 48 जेडडी 7126 को जप्त किया गया। जप्त वाहन को थाना गंज बैतूल की अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है। उक्त प्रकरण में वाहन चालक/वाहन मालिक के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण तैयार किया गया है, जिसे न्यायालय अपर कलेक्टर, बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1.60 करोड़ रुपए से हो रहा कॉलेज चौक का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण

खत्म होगा यातायात का दबाव, जाम से मिलेगी राहत

बैतूल। शहर के सबसे व्यस्त कॉलेज चौक पर लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित आवागमन की समस्या से अब लोगों को जल्द ही निजात मिलने वाली है। कॉलेज चौक पर सडक़ चौड़ीकरण और सौंदयीकारण का कार्य शुरू हो गया है। फिलहाल पुलिया निर्माण की जा रही है। इसके बाद कॉलेज चौक के सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण का कार्य किया जायेगा। बताया जा रहा है कि यह शहर का पहला ऐसा चौराहा होगा, जिसे विशेष तकनीकी डिजाइन के आधार पर विकसित किया जा रहा है, जिससे चौराहे से गुजरने वाले वाहनों का दबाव काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। कॉलेज चौक के लिए तैयार की डाइंग और डिजाइन के अनुसार चौराहे के चारों मार्गों पर लेफ्ट टर्न के लिए अलग-अलग पासिंग मार्ग बनाए जा रहे हैं। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद वाहन चालकों को बीच चौराहे में प्रवेश कर टर्न लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेफ्ट टर्न करने वाले वाहन सीधे बगल से निकल जाएंगे, जबकि केवल सीधे जाने वाले वाहन ही चौराहे के मध्य भाग से गुजरेंगे। इससे चौराहे पर वाहनों का जमा कम होगा और जाम जैसी स्थिति से राहत मिलेगी।

यातायात को ध्यान में रखते हुए चौड़ीकरण – कॉलेज चौक पर यातायात के दबाव को ध्यान में रखते हुए चौक का चौड़ीकरण किया जा रहा है। यहां मौजूद पुरानी पुलिया को हटाकर उसकी जगह 36 मीटर लंबी सीसी पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। पुलिया 4 बाय 2 साइज साइज की बनाई जा रही है। जिसमें 4 फीट चौड़ाई और 2 मीटर ऊंचाई निर्धारित की गई है। पुलिया निर्माण से बरसात के मौसम में जल निकासी की समस्या का भी स्थायी समाधान होगा। कॉलेज चौक के चौड़ीकरण और सौदयीकरण पर कुल लगभग 1.60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस राशि में पुलिया निर्माण के साथ-

साथ चौराहे से जुड़ी चारों सडक़ों पर 25 से 30 मीटर लंबाई तक रोड वाइडिंग का कार्य शामिल है।

पैदल यात्रियों के लिए 5 फीट चौड़ा रहेगा फुटपाथ– कॉलेज चौक पर चौराहे का सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण के साथ-साथ पैदल यात्रियों की सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया है। यहां पैदल यात्रियों के लिए 5 फीट चौड़े फुटपाथ का निर्माण भी किया जायेगा। जिससे कि पैदल चलने वाले यात्रियों को वाहनों के बीच से गुजरना न पड़े। इससे चौराहे पर हादसे का अंदेशा भी कम हो जायेगा। बताया गया कि फिलहाल पाइप लाइन शिफ्टिंग के बाद अब पुलिया का निर्माण करेगे। इसके बाद कॉलेज चौक के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण पर कार्य होगा। अभी पाइप लाइन शिफ्टिंग और पुलिया निर्माण के लिए सडक़ को डायवर्ट कर दिया है। जिससे वर्तमान में कॉलेज चौक से गंज वाले वाले वाहनों की आवाजाही चालू है।

कॉलेज चौक पर ट्रैफिक सिग्गल लगाने का भी प्रस्ताव– बताया जा रहा है कि कॉलेज चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे आवागमन और अधिक सुचारू किया जा सके। बता दे कि इस चौराहे से रोजाना बड़ी संख्या में यात्री सारणी, आमला आदि क्षेत्रों के लिए बस में सवार होते है। वहीं शहर के व्यस्ततम चौराहा होने के कारण लंबे समय से कॉलेज चौक के सौंदर्यीकरण की मांग उठ रही थी। जिसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की पहल पर इस चौक के सौंदर्यीकरण के लिए करीब सवा करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से इस चौक पर विभिन्न कार्य कराए जाने है। निर्माण पूरा होने के बाद कॉलेज चौक का स्वरूप ही पूरी तरह से बदल जायेगा और लोगों को अच्छे आवागमन की सुविधा मिलने के साथ-साथ बार-बार जाम की स्थिति से निजात मिलेगी।

इनका कहना है –

कॉलेज चौक पर पुलिया निर्माण के लिए कार्य चल रहा है। इसके बाद चौक के चौड़ीकरण और सौदर्यीकरण का काम शुरू होगा। यह कार्य करीब 1.60 करोड़ की लागत से होना है।

– **सतीश मटसेनिया,** सीएमओ, नगरपालिका बैतूल

भव्य शोभायात्रा में शिव ज्योतिर्लिंग की झांकी सजाकर दिया परमात्मा अवतरण का संदेश

बैतूल। ब्रह्माकुमारीज के सारनी सेवा केंद्र द्वारा आगामी महाशिवरात्रि पर्व पर के उपलक्ष में शिव जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें सारनी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में शोभायात्रा, कलश यात्रा एवं झांकी के माध्यम से शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताया जाएगा। इसी कड़ी में ग्राम सलैया, छुरी में शोभायात्रा का आयोजन किया गया। जिसमें शिव भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग को चार पहिया वाहन के ऊपर रथ सजा कर स्थापित किया गया तथा साथ ही नंदीगण को भी सजाया गया। यह यात्रा छुरी के खेड़ापति शिव मंदिर से शुरू होकर छुरी, सलैया का चक्र लगाकर बागडोना पहुंची। जिसमें ब्रह्मकुमारीज के सारणी क्षेत्र के अनुयायियों ने हिस्सा लेकर जन मानस को पर्चों और अनाउंसमेंट के माध्यम से शिव संदेश दिया। ब्रह्माकुमारी सारणी की प्रमुख ब्रह्माकुमारी

सुनीता दीदी ने बताया की ब्रह्मकुमारीज में हर वर्ष शिवरात्रि पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है तथा यह वर्ष ब्रह्मा कुमारीज में नव दशकोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि परमात्मा शिव द्वारा रचित इस विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएं करते हुए 90 वर्ष हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि ब्रह्माकुमारीज में मुख्य रूप से राजयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके द्वारा परमात्मा शिव का सत्य परिचय प्राप्त कर उस से संबंध स्थापित करना सहज हो जाता है। प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करने से जीवन में कई आध्यात्मिक शक्तियों और गुणों का विकास होता है। इस राजयोग का प्रशिक्षण ब्रह्माकुमारी विद्यालय में आकर कोई भी निशुल्क प्राप्त कर सकता है।

संक्षिप्त समाचार

हिट एंड रन के प्रकरण में आर्थिक मदद जारी

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने सड़क दुघर्टना में मृतक के परिजन को 15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत कर जारी कर दी है। हिट एंड रन के प्रकरण की जानकारी देते हुए संयुक्त कलेक्टर व नोडल अधिकारी सुश्री निकिता तिवारी ने बताया कि सागर जिले के ग्राम किशनगढ निवासी श्रीमती नंदनी पत्नि चैनसिंह कुशवाह की सड़क दुघर्टना में मृत्यु हो जाने पर मृतिका के परिजन श्रीमती जमनाबाई पति सीताराम कुशवाह को 15 हजार रुपए की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 38 मेधावी बालिकाएँ होंगी सम्मानित

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शिक्षण वर्ष 2024-25 में आयोजित 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना के तहत कुल 1.90 लाख (एक लाख नब्बे हजार रुपए) की प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी। योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं की 18 एवं कक्षा 12वीं की 20, इस प्रकार कुल 38 मेधावी बालिकाओं को प्रति बालिका क्रमशः 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह सम्मान राशि बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने और उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से दी जा रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा ने बालिकाओं की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बेटियाँ आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की योजनाएँ न केवल बालिकाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं, बल्कि समाज में बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश भी देती हैं। कार्यक्रम के माध्यम से मेधावी छात्राओं को सम्मानित कर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे वे अपने सपनों को साकार कर समाज व राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

आयुर्वेद चिकित्सालय टिकारी में किया जा रहा गर्भसंस्कार कार्यक्रम

बैतूल (निप्र)। जिला आयुर्वेद चिकित्सालय टिकारी में गर्भवती महिलाओं के लिए प्रति मंगलवार एवं शुक्रवार नियमित रूप से गर्भसंस्कार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार-विहार, योग, प्राणायाम, ध्यान, संगीत चिकित्सा तथा सकारात्मक जीवनशैली के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। साथ ही गर्भावस्था के दौरान होने वाली सामान्य समस्याओं के आयुर्वेदिक समाधान भी बताए जाते हैं, ताकि माताएं गर्भकाल को स्वस्थ और संतुलित ढंग से पूरा कर सकें। जिला आयुष अधिकारी डॉ.योगेश चौकीकर ने बताया कि गर्भसंस्कार कार्यक्रम से गर्भस्थ शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायता मिलती है। इससे मां के तनाव, चिंता एवं अवसाद में कमी आती है तथा प्रसव पीड़ा को सहन करने की क्षमता में वृद्धि होती है। कार्यक्रम शिशु के संस्कार, स्मरण शक्ति एवं बुद्धि विकास में सहयोग प्रदान करता है। इसके साथ ही मां और शिशु दोनों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है तथा सकारात्मक सोच एवं भावनात्मक संतुलन का विकास होता है। जिला आयुर्वेद चिकित्सालय टिकारी द्वारा क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं से अपील की गई है कि वे इस निःशुल्क कार्यक्रम का लाभ उठाएं और स्वस्थ मातृत्व की दिशा में आयुर्वेद की इस प्राचीन विधा को अपनाएं।

कृषि रथ के माध्यम से किसानों को किया जा रहा जागरूक

हरदा (निप्र)। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग प्रदेश में वर्ष 2026 को 'कृषि वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन के निर्देशन में जिले के तीनों विकासखंडों में कृषि रथ का संचालन किया जा रहा है। उप संचालक कृषि जे.एल. कास्दे ने बताया कि कृषि रथ के साथ कृषि विज्ञान केंद्र, कोलीपुरा के वैज्ञानिक, कृषि विभाग एवं संबद्ध विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा किसानों से सीधा संपर्क कर ई-विकास प्रणाली से उर्वरक क्रय करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। साथ ही नरवाई प्रबंधन, ग्रीष्मकालीन मूंग फसल के स्थान पर उडद, मूंगफली, तिल आदि फसलो को प्रोत्साहन, प्राकृतिक व जैविक कृषि करने हेतु प्रोत्साहन, मृदा स्वास्थ कार्ड के आधार पर उर्वरको की संतुलित मात्रा का उपयोग करने और भूमि पर बोई गई फसल अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग करने आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। इसके अलावा विभाग द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ किसानों को समसामयिक सलाह भी प्रदान की जा रही है। श्री कास्दे ने बताया कि जिले के विकासखंडो में संचालित कृषि रथों द्वारा जिले की 162 ग्राम पंचायतो में भ्रमण किया गया है।

स्नेह सम्मेलन व पुरस्कार वितरण समारोह में प्रतिभाओं का सम्मान

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस,शासकीय महाविद्यालय विदिशा में तीन दिवसीय आयोजन सम्पन्न

विदिशा (निप्र)। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय महाविद्यालय विदिशा में वार्षिक कैलेंडर के अनुसार 5 से 7 फरवरी तक तीन दिवसीय स्नेह सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। इस दौरान महाविद्यालय में क्रीड़ा, साहित्यिक, रचनात्मक तथा कलात्मक-सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ।

कार्यक्रम का समापन 7 फरवरी को भव्य पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। समारोह विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ , कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र रघुवंशी ने की। कार्यक्रम में विदिशा नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शर्मा, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा नेता श्री श्याम सुंदर शर्मा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती मंजरी जैन सहित जनभागीदारी समिति के सदस्य श्री कौशल मांझी, श्री दीपक शर्मा, श्री गौरव माहेश्वरी, श्री रामू जी, श्री बृजेश जी, श्री पवन शर्मा, श्री रामेश्वर जी, श्री मनीष जी, श्री सचिन तिवारी, श्री भरत शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. वनिता बाजपेई ने वर्ष भर की गतिविधियों का

प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि विधायक श्री मुकेश टंडन ने विद्यार्थियों को महाविद्यालय में अध्ययन हेतु प्रेरित करते हुए शासन की विभिन्न छात्रहितैषी योजनाओं की जानकारी दी और उनका लाभ उठाने का आह्वान किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री सुरेंद्र रघुवंशी ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं और महाविद्यालय की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। श्री श्याम सुंदर शर्मा ने भारतीय परंपराओं और जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए विद्यार्थियों को व्यक्तित्व विकास हेतु प्रेरित किया। श्रीमती मंजरी जैन ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को युवा शक्ति की सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों दिशाओं से अवगत कराते हुए कहा कि यदि युवा ऊर्जा सार्थक कार्यों में लगे तो देश की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता, और इसमें विद्यार्थियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान विधायक श्री टंडन से विद्यार्थियों के हित में महाविद्यालय परिसर में टीन शेड निर्माण की मांग की गई, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए विद्यार्थियों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन राजनीतिशास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक श्री भगवत सिंह पाल ने किया। क्रीड़ा गतिविधियों एवं पुरस्कारों का वाचन डॉ. अजय सिंह हजारी द्वारा किया गया। स्नेह सम्मेलन की प्रभारी एवं वाणिज्य विभाग की सहायक प्राध्यापक श्रीमती श्वेता सोलंकी ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह में महाविद्यालय के डॉ. सत्येंद्र सिंह, डॉ. सुनील कुमार जैन, डॉ. डीपीएस नरवरिया, डॉ. राज कुमार भीमटे, डॉ. रश्मि यादव, डॉ. प्रमोद कुमार सेन, डॉ. ब्रजेश साहू, श्री सोहन कुमार, डॉ. निमिषा वर्मा, श्री सुरेंद्र नायक, श्री नीलेश प्रजापति, श्रीमती दीप्ति भार्गव सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उत्साहपूर्वक उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच प्रदान करते हुए शैक्षणिक वातावरण को उत्सवमय बना दिया।

सुल्तानपुर में 10 फरवरी को आयोजित होगा जिला स्तरीय युवा संगम मेला

रायसेन (निप्र)। जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार 10 फरवरी 2026 को नगर परिषद प्रांगण सुल्तानपुर में जिला स्तरीय युवा संगम मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा कौशल विकास विभाग के संयुक्त तत्वधान में आयोजित यह युवा संगम मेला 10 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक आयोजित किया गया है। इस युवा संगम मेले के माध्यम से युवाओं को विभिन्न कम्पनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के साथ ही शासन की स्वरोजगारमूलक योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इस जिला स्तरीय युवा संगम मेले में नवभारत फर्टीलाइजर भोपाल, भास्कर मण्डीदीप, आईपीएस भोपाल, इंसुलेटर एण्ड इलेक्ट्रिकल्स मण्डीदीप, यश्यवी ग्रुप मण्डीदीप, सागर मेनिफेक्चर तामोट, होम हेल्प सेंटर रायसेन, हकाई सिकरोटी मण्डीदीप, आर सेठी रायसेन, वोल्वो आयशर वगरोदा, शुभम एंटरप्राइजेज भोपाल, एसआईएस सिंगरोली जिला रायसेन द्वारा विभिन्न पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी।

विदिशा के कृषि उपकरण निर्माताओं ने देवास स्थित जॉन डियर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का किया एक्सपोजर विजिट

विदिशा (निप्र)। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, विदिशा द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जिले की कृषि उपकरण निर्माण इकाइयों के लिए देवास स्थित जॉन डियर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेंटर का एक्सपोजर विजिट आयोजित किया गया। इस औद्योगिक भ्रमण में जिले की कुल 8 कृषि उपकरण निर्माता इकाइयों ने सहभागिता की। एक्सपोजर विजिट के दौरान प्रतिभागी इकाइयों को जॉन डियर के अत्याधुनिक ऑपरेशन एरिया का विस्तृत भ्रमण कराया गया। भ्रमण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा कृषि उपकरण निर्माण की आधुनिक तकनीकों, उत्पादन प्रक्रियाओं तथा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की जानकारी दी गई। साथ ही वेंडर डेवलपमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तार से मार्गदर्शन प्रदान किया गया। जॉन डियर की टीम ने स्थानीय इकाइयों को उत्पादन प्रक्रिया में सुरक्षा मानकों का पालन, उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित करने, तथा पर्यावरणीय और नैतिक मानकों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। इकाइयों को यह भी सुझाव दिया गया कि वे अपने-अपने यूनिट की विस्तृत ब्रोशर और प्रोफाइल जॉन डियर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के साथ साझा करें , ताकि भविष्य में संभावित व्यावसायिक सहयोग की संभावनाएं बन सकें। इस अवसर पर जॉन डियर के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वेंडर चयन प्रक्रिया के तहत उनकी टीम शीघ्र ही विदिशा जिले की कृषि उपकरण निर्माण इकाइयों का स्थल निरीक्षण (फैक्ट्री विजिट) करेगी। यह एक्सपोजर विजिट स्थानीय उद्योगों के लिए तकनीकी उन्नयन, बाजार विस्तार तथा बड़े औद्योगिक समूहों से जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच श्रद्धा शिखर चौरागढ़ महादेव मंदिर पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब

मेले की व्यवस्था की कमान संभाले पूरी प्रशासनिक टीम मुस्तैद

नर्मदापुरम (निप्र)। पचमढ़ी महादेव मेले के दूसरे दिन भी पचमढ़ी में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी। ऊंची-ऊंची चढ़ाई और दुर्गम मार्ग भी श्रद्धालुओं के उत्साह और अटूट विश्वास को डिगा नहीं पा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के प्रति गहन आस्था रखते हुए श्रद्धालु बड़े एवं भारी त्रिशूल लेकर कठिन और लंबा रास्ता तय कर चौरागढ़ मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशानुसार संपूर्ण प्रशासनिक अमला मेले में तैनात रहकर श्रद्धालुओं की सहायता में जुटा है। स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता से लेकर मार्गदर्शन तक सभी व्यवस्थाएं सतत रूप से सुनिश्चित की जा रही हैं। मेले की व्यवस्थाओं का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु जैन एवं पिपरिया एसडीएम श्री आकिप खान ने मुख्य मंदिर स्थल चौडेश्वर महादेव पहुंचकर मार्ग का जायजा लिया। इस

दौरान सीईओ श्री जैन ने श्रद्धालुओं से संवाद कर व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी भी ली। कलेक्टर के निर्देशों के परिपालन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा चौरागढ़ मार्ग पर संचालित खाद्य दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की वैधता, गुणवत्ता और साफ-सफाई की जांच की गई। दुकान संचालकों को स्वच्छता बनाए रखने हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इसी प्रकार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्रीमती रिंकू शर्मा द्वारा मेले के विभिन्न पॉइंट्स पर पहुंचकर वाहनों की जांच की गई। अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही बिना पंजीयन एवं बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों को समझाइश देकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव इंतजाम किए गए हैं। नगर पालिका द्वारा फायर ब्रिगेड के माध्यम से मार्गों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे धूल की समस्या से राहत मिले और यात्रियों को सुगम आवागमन मिल सके। लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों के खराब शोल्डर को मुरम-बजरी से दुरुस्त किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम निर्धारित स्थानों पर आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक कुल 360 वाहनों को परमिट जारी किए जा चुके हैं। आपदा प्रबंधन के तहत होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ की टीम लगातार तैनात है।

बोर्ड परीक्षा 2025-26 की गोपनीय सामग्री का वितरण प्रारंभ

बैतूल (निप्र)। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, भोपाल के निर्देशानुसार बोर्ड परीक्षाएँ सत्र 2025-26 की गोपनीय सामग्री का वितरण कार्य जिले में सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से किया जा रहा है। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार समन्वय संस्था शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, बैतूल से आज दिनांक 06 फरवरी 2026 को कुल 103 परीक्षा केंद्रों की गोपनीय सामग्री का वितरण सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। शेष 24 परीक्षा केंद्रों की सामग्री का वितरण कार्य कल दिनांक 07 फरवरी 2026 को किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी श्री भूपेंद्र वरकड़े ने बताया कि वितरण प्रक्रिया कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल, नोडल अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी बैतूल के प्रतिनिधि के रूप में सहायक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों, समन्वय संस्था के प्राचार्य तथा 1+4 पुलिस बल की सशक्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। इस दौरान स्ट्रांग रूम खोलकर प्रश्न पत्रों सहित अन्य गोपनीय सामग्री का विधिवत वितरण किया गया। परीक्षा की पारदर्शिता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रवार केंद्र अध्यक्ष एवं सहायक केंद्र अध्यक्षों को सीएम राइज बस के माध्यम से सुरक्षा गार्ड के साथ संकलन केंद्र के लिए रवाना किया गया। प्रशासन द्वारा पूरी प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखी जा रही है, जिससे बोर्ड परीक्षाओं का संचालन शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

एसएटीआई के विद्यार्थियों ने एमएसएमई जागरूकता कार्यक्रम में शासकीय खरीद प्रक्रिया को जाना

विदिशा (निप्र)। सम्राट अशोक टेक्नॉलाजीकल इंस्टीट्यूट (एसएटीआई) विदिशा मे रोजगार और स्वरोजगार की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) द्वारा शासकीय खरीद प्रक्रिया पर एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें 60 से अधिक छात्र छात्राओं को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के प्रायोजक आफिस आफ द डेवलपमेंट कमिश्नर सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार हैं और कार्यक्रम के आयोजक उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडनैप) है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों में स्वरोजगार की भावना विकसित करना, एमएसएमई और शासकीय योजनाओं की जानकारी देना, स्थानीय स्तर पर व्यावसायिक अवसरों से परिचित करवाना और सबसे महत्वपूण शासकीय खरीद प्रक्रिया में में विक्रेता के रूप में किस प्रकार सम्मिलित हो सकते हैं बताया गया। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से स्वरोजगार क्यों, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, शासकीय योजनाऐं और जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता के रूप में श्रीमती जयंती कुमारी, सहायक प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सतीश पवार, असिस्टेंट प्रो., एसएटीआई विदिशा, सुश्री रितु साहू, सहायक प्रबंधक एवं जिला समन्वयक सेडमैप विदिशा ने अपनी जानकारी साझा की। कार्यक्रम अवसर पर डॉ. वायके जैन, डायरेक्टर एसएटीआई इंजीनियरिंग विदिशा, डॉ आलोक जैन, डीन एकेडमिक, डॉ. कनक सक्सेना, एचओडी सीएसई, डॉ. सुनील जोशी, दिव्य रिशि साहू असिस्टेंट प्रो. उपस्थित थे कार्यक्रम का संचालन एवं समन्वयन दिनेश कुमार गावड़े, जिला समन्वयक, सेडमैप विदिशा, द्वारा किया गया।

ग्राम रंगई में जनभागीदारी से पौधरोपण, मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया शुभारंभ

सार्वजनिक भूमि के सदुपयोग व गौसंवर्धन पर दिया जोर, ग्रामीण विकास की भूमिका बताई अहम

विदिशा (निप्र)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज विदिशा जनपद की ग्राम रंगई में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण और जनसहभागिता का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर सार्वजनिक हितों की पूर्ति हेतु की गई यह पहल अनुकरणीय है। उन्होंने उल्लेख किया कि कई स्थानों पर सार्वजनिक भूमि के अभाव में शासकीय भवनों के निर्माण कार्य प्रभावित होते हैं, ऐसे में उपलब्ध भूमि का सुव्यवस्थित उपयोग आवश्यक है।

मंत्री श्री पटेल ने विशेष रूप से गौशालाओं के चारों ओर बड़ी प्रजाति के पौधे लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे गायों के संवर्धन, स्वास्थ्य संरक्षण एवं अनुकूल वातावरण निर्माण में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मूक पशुओं को सड़कों पर घूमने से रोकने में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार तकनीकी सहयोग और वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा सकती है, परंतु सेवा कार्यों का वास्तविक क्रियान्वयन समाज के हाथों में होता है। उन्होंने विदिशा जिले को इस दिशा में अग्रणी बताते हुए सराहना की। विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन ने अपने उद्बोधन में कहा कि मध्यप्रदेश को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लाने के अभियानों के प्रभावी क्रियान्वयन में ग्रामीण विकास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जिले में गौशालाओं में गौवंश संवर्धन हेतु किए जा रहे प्रयासों को विशेष रूप से रेखांकित किया। पौधरोपण कार्यक्रम में मंत्री श्री पटेल, विधायक श्री टंडन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यह आयोजन पर्यावरण संतुलन, पशुधन संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी का सशक्त उदाहरण बना। इस अवसर पर विभिन्न प्रजाति के 251 पौधे रोपित किए गए है। उक्त कार्य में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी, जनपद सदस्य श्रीमती ममता फूल सिंह यादव, सरपंच श्रीमती अर्चना अमित कुशवाह के अलावा श्री संदीप सिंह डोंगर समेत अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक व विभिन्न विभागो के अधिकारियों के द्वारा सहभागिता निभाई गई है।

कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकल रही किसान जागृति यात्रा :24 फरवरी को नर्मदापुरम पहुंचेगी

अमेरिकी कृषि समझौते के खिलाफ जनसभा

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम संयुक्त किसान (गैर-राजनीतिक) मोर्चा कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसान जागृति यात्रा निकाल रहा है। यह यात्रा 24 फरवरी को नर्मदापुरम जिले में पहुंचेगी। किसान नेताओं के अनुसार, यात्रा का उद्देश्य किसानों के मुद्दों को देशभर में उजागर करना है और उनकी आवाज को सरकार तक पहुँचाना है।

यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी : यात्रा 7 फरवरी को कन्याकुमारी से एक विशाल जनसभा के साथ शुरू हुई। इसे महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रवाना किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों के किसान नेता मौजूद रहे, जिनमें जगजीत सिंह डल्लेवाल (पंजाब), क्क्रुर्बुरु शांताकुमार (कर्नाटक), पी. आर. पांड्यंन और पी. अय्यकन्नू (तमिलनाडु), अभिमन्यु कोहाड़ (हरियाणा), और इंदरजीत पन्नीवाला (राजस्थान) शामिल थे। यात्रा के दौरान किसान नेताओं ने भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते को किसानों के हितों के खिलाफ बताया। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि अमेरिकी कृषि उत्पादों पर नॉन-टैरिफ प्रतिबंध हटने से भारतीय बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए खुल जाएगा और इससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा। शांताकुमार ने अमेरिका में किसानों को मिलने वाली भारी सब्सिडी और भारत में कम सहायता का मुद्दा उठाया।

किसानों की प्रमुख मांग: एमएसपी गारंटी कानून : पी. अय्यकन्नू ने बताया कि एमएसपी गारंटी कानून किसानों की प्रमुख मांग है और इसे लागू करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही किसान नेता बाजारों में उचित मूल्य और फसलों की सुरक्षा की बात भी उठाते रहे। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के जिला प्रवक्ता केशव साहू ने बताया कि यात्रा 18 फरवरी 2026 को नर्मदापुरम जिले में प्रवेश करेगी।

मंत्री ने माना..... ही देते हैं रिश्वतखोरों को प्रश्रय ?

राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के 'करप्शन' वाले बयान ने सियासत की हांडी में उबाल ला दिया है। कांग्रेस इसे लपकने की कोशिश में है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा कर्नाटक की '40 फीसदी कमीशन' वाली हार को भूल गई है ? जब राजस्व विभाग के मुखिया ही कहें कि 'थोड़ा बहुत चलता है', तो नीचे वाले इसे 'पूरी छूट' मान लेते हैं। चर्चा तो यह भी है कि जिलों के कप्तान अपने मातहतों के भ्रष्टाचार को ढाल प्रदान करते हैं। तभी तो नामांतरण, सीमांकन और आय-आदि प्रमाणपत्रों का खेल बिना 'सेवा' के आगे नहीं बढ़ता। जब मंत्री दौरे पर जाते हैं और कलेक्टर पहले ही सफाई देने लगें कि थोड़ी 'गलती-सलती होगी तो सुधार लेंगे', तो समझ लेना चाहिए कि सुशासन के दावों के पीछे करप्शन का कैसा गठजोड़ फल-फूल रहा है। यह सुशासन है या 'कमीशन-शासन'?

मोहन का मंत्रालय

आशीष चौधरी

ई-ऑफिसः जनता से दूरी, फाइलों से यारी

मुख्य सचिव अनुराग जैन के महत्वाकांक्षी 'ई-ऑफिस' प्रोजेक्ट ने सरकारी कामकाज की गति तो बढ़ा दी है, लेकिन मंत्रियों का भोपाल प्रेम घटा दिया है। अब फाइलों के लिए विशेष वाहक को मंत्री के गृह जिले तक दौड़ नहीं लगानी पड़ती, टैबलेट के एक क्लिक पर फाइलें निपट रही हैं। नतीजा? मंत्री अब भोपाल के बंगलों पर नजर नहीं आते। ई-ऑफिस ने काम तो आसान किया, लेकिन आम जनता के लिए मंत्रियों से मिलना दूभर कर दिया है। मंत्री जी अब प्रभार के जिले या अपनी विधानसभा में डेरा डाले रहते हैं। कामकाज तो डिजिटल हो गया, लेकिन जनता की समस्याओं का 'एनालॉग' समाधान कौन करेगा?

कैबिनेट में 'ऑनलाइन' हाजिरी

आज मंगलवार है और सबकी निगाहें कैबिनेट की बैठक पर हैं। एक कद्दावर मंत्री जी, जो पिछली बार नदारद थे और दिल्ली दरबार के चक्कर लगा रहे थे, उनकी नाराजगी बरकरार है या खत्म हुई, यह सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों की मानें तो मंत्री स्वयं व्यक्तिगत रूप से शामिल न होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि खफा चल रहे मंत्री जी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं या फिर 'दिल्ली दूर है' का सिग्नल भेजते हैं। क्या ऑनलाइन जुड़ना सरकार में चल रही आंतरिक दूरियों को पाटने का नया तरीका है?

मंत्री बड़ा या साहब?

राजधानी के एक रसूखदार विभाग के कमिश्नर साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) इन दिनों चर्चा में है। साहब हफ्ते में तीन-चार दिन घंटों मीटिंग लेते हैं और दूरदराज के अधिकारियों को 'खरी-खोटी' सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हालत यह है कि अधिकारी, इस दौरान मुख्यमंत्री या मंत्री कार्यालय का फोन उठाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे। पिछले दिनों एक मंत्री जी ने काम के लिए फोन लगाया, तो जवाब मिला– 'साहब कमिश्नर की मीटिंग में हैं।' अब सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना गया मंत्री बड़ा है या फाइलों में डूबे कमिश्नर साहब? अधिकारी अब दबे स्वर में पूछने लगे हैं कि उन्हें जनता का काम करना है या सिर्फ वीसी में हाजिरी बजानी है।

विभागों के प्रस्ताव, नयी योजना नहीं !

राज्य सरकार के बजट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। बजट में सरकार कौन से नयी योजना ला रही है या पुरानी योजनाओं पर ताला लगेगा। अंदर की बात यह है कि बजट के लिए विभागों से प्राप्त प्रस्तावों में नयी योजना का अभाव है। इसकी वजह सरकार की माली हालत बतायी जा रही है। कुछ विभागों ने नयी योजनाओं के लिए प्रस्ताव तो भेज दिए है लेकिन उन पर कैंची चलने की पूरी आशंका है। अब देखना है कि सरकार बजट को कैसे मन मोहक बनाती है।

मुख्य सचिव की समीक्षा केंद्रीय बजट के अनुरूप परियोजनाओं और योजनाओं के प्रस्ताव भेजने के निर्देश

भोपाल। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने विभाग अध्यक्षों सहित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव से अपेक्षा की है कि वे केंद्रीय बजट के प्रावधानों के अनुरूप परियोजनाएं और योजनाएं तैयार कर भारत सरकार को भेजें इससे मध्यप्रदेश के प्राथमिकता क्षेत्र को अत्यधिक लाभ मिल सके। मंत्रालय में सोमवार को बैठक में मध्यप्रदेश विधान सभा के बजट सत्र की तैयारियों, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों की पूर्ति, सुशासन के बिंदुओं सहित मंत्रि-परिषद के निर्णयों के पालन की समीक्षा की। मुख्य सचिव श्री जैन ने मध्यप्रदेश विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा कर निर्देश दिए हैं कि पिछले सत्रों के शून्यकाल सूचनाओं सहित अपूर्ण उत्तर वाले प्रश्न, आश्वासन और लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं के लंबित मामले यथाशीघ्र पूर्ण करें। उन्होंने विभागीय परामर्शदात्री समितियों की बैठक करने के साथ ही विधानसभा को विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि आर्थिक ग्रोथ में पूंजीगत खर्चों का अहम योगदान होता है। अपर मुख्य सचिव श्री मनीष रस्तोगी ने बताया कि अन्य वर्षों की तुलना में इस वित्त वर्ष में पूंजीगत खर्चों में वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति बेहतर है।

कृषि और पशुपालन किसानों के लिए बन रहा लाभकारी व्यवसाय

भोपाल। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उत्थान, शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। शासन द्वारा कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कृषि और पशुपालन अब न केवल लाभ का व्यवसाय बन गया है, बल्कि इससे किसानों और पशुपालकों को नई पहचान भी मिल रही है। छिंदवाड़ा जिले के चौरई विकासखंड के ग्राम बांकानागनपुर के नवीन रघुवंशी भी उन्हीं किसानों और पशुपालकों में से एक हैं। श्री रघुवंशी ने पशुपालन विभाग की राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजना का लाभ लेकर बकरी पालन को एक सशक्त और लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित किया है। सीमित संसाधनों से शुरू हुई उनकी यह पहल आज आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक प्रबंधन के कारण क्षेत्र में एक मॉडल बकरी फार्म के रूप में पहचान बना चुकी है। श्री रघुवंशी बताते हैं कि एनएलएम योजना के अंतर्गत स्वीकृत उनके इस बकरी फार्म में सिरोही नस्ल की कुल 175 बकरियाँ, बकरे एवं उनके बच्चे उपलब्ध हैं। फार्म को मॉडल स्वरूप में विकसित किया गया है, जिसमें बीमार बकरियों के लिए पृथक क्वारंटाइन शेड, बच्चों के लिए अलग कमरे तथा बकरियों के बैठने के लिए 4 फीट ऊँचाई पर प्लाई प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसी प्लेटफॉर्म के नीचे कड़कनाथ मुर्गी का पालन भी किया जा रहा है, जिससे अतिरिक्त आय का स्रोत विकसित हुआ है।

बकरी फार्म की कुल लागत लगभग 1 करोड़ रुपये है, जिसमें भारत सरकार द्वारा 50 लाख रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में 25 लाख रुपये की राशि श्री नवीन रघुवंशी को प्रदाय की जा चुकी है। इस आर्थिक सहयोग से फार्म को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया गया है। बकरियों के पोषण के लिए फार्म में तीन प्रकार की नेपियर घास का उत्पादन किया जा रहा है। दाना बनाने की मशीन एवं चैफ कटर जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। ब्रीडिंग के उद्देश्य से उच्च गुणवत्ता के बकरे रखे गए हैं, जिनमें एक बकरे की कीमत लगभग 2 लाख रुपये है। बेहतर पोषण और प्रबंधन के कारण बकरियों का स्वास्थ्य एवं उत्पादन स्तर उत्कृष्ट बना हुआ है।

नदी बनी 'मधुशाला', पानी के बीच धधक रही थीं भट्टियां

पुलिस पहुंची तो कपडों के नीचे मिली शराब की कई टंकियां

अशोकनगर। मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिला पुलिस द्वारा शराब माफियाओं पर बड़ी कार्यवाही की गई है। पुलिस ने एक नदी में चल रही शराब फैक्ट्री को पकड़ा है, जहां से 500 लीटर अवैध कच्ची शराब और लगभग 4 हजार लीटर लहान मिला। पुलिस ने इस सामग्री को नष्ट कर दिया है। यह छापा माधोगढ़ गांव में पुलिस ने सुबह 4 बजे डाला। इस दौरान पूरे ग्राम की तलाशी ली गई, जहां से पुलिस को एक दुकान से कच्ची शराब मिली। वहीं, जब ग्राम के पास से निकली भादोन नदी पर पुलिस पहुंची तो पुलिस को कई शराब भट्टियां जलते

हुए मिलीं, जिन पर कच्ची शराब बनाने का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान एसडीओपी विवेक शर्मा ने बताया कि पुलिस ने देर रात यहां छापा डाला। यहां लंबे समय से शराब बनाने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद सैकड़ों पुलिस जवानों के साथ यहां छापा मारा। यहां से बड़ी संख्या में अवैध शराब और शराब बनाने की सामग्री मिली। माफिया इस शराब को करीला मेले में खपाने की फिराक में थे। इस दौरान पुलिस को कई स्थानों पर शराब बनते हुए मिली। वहीं, बनी हुई शराब को ढूंढने के लिए पुलिस को घंटों नदी की खाक छाननी पड़ी। पुलिस को शराब और लहान कहीं जमीन में तो, कहीं नदी में सूख रहे घाघरे सहित कपड़ों के नीचे जमीन में गड़ी टंकियों में भरी मिली। कचनार थाना प्रभारी पूनम सेलर ने बताया कि इस कार्रवाई में 6 थानों की पुलिस व सैकड़ों जवान शामिल रहे। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से दूर - दूर तक जवान तैनात किए थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।

भोपाल में गोमांस-पानी के मुद्दे पर जबरदस्त प्रदर्शन

कांग्रेस ने किया निगम दफ्तर का घेराव, महापौर सहित एमआईसी सदस्यों का रावण रूपी पुतला फूंका

भोपाल। भोपाल में पिछले एक महीने से सुर्खियों में बने गोमांस और गंदे पानी की सप्लाई के मुद्दे पर सोमवार को बड़ा प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस नेता रविंद्र साहू झूमरवाला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आईएसबीटी स्थित निगम दफ्तर का घेराव किया और महापौर मालती राय और एमआईसी का रावण रूपी पुतला फूंका। इससे पहले पुलिस के साथ धक्का-मुक्की हुई और जोरदार नारेबाजी की गई। बता दें कि कांग्रेसी महापौर का 11 सिर वाला कटआउट लेकर पहुंचे थे, जिसमें 10 सिर अन्य जिम्मेदारों के हैं। बता दें कि इंदौर में दूषित पानी पीने से 33 लोगों की जान चली गई। भोपाल में भी ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है। कई इलाकों में सीवेज के साथ ही पानी की लाइन है। इससे पानी गंदा आ रहा है। दूसरी ओर, वार्ड ऑफिसों में जल सुनवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही हो रही है। नाले के पानी को भी पीने योग्य बताया जा रहा है। पिछले दिनों पड़ताल में वार्ड के कर्मचारी ने नाली के पानी को पीने योग्य बता दिया था। कांग्रेस नेता

साहू ने बताया कि कहीं पानी के चैंबर में सीवेज का पानी मिल रहा है तो कहीं गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। इससे लोग बीमार भी हो रहे हैं। इसके अलावा स्लॉटर हाउस में गोमांस मिलने का मामला भी गंभीर है। अब तक छोटे कर्मचारियों पर ही कार्रवाई हुई है, लेकिन जिम्मेदार महापौर और एमआईसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एमआईसी मीटिंग से ही स्लॉटर हाउस का प्रस्ताव पास हुआ था। बता दें कि जहांगीराबाद थाना प्रभारी मान सिंह चौधरी ने 24 दिसंबर 2025 को एक एफआईआर दर्ज की। इसमें 7 दिन पहले, 17 दिसंबर को कंटेनर नंबर यूपी 15 जेटी 4286 में मांस मिलने का हवाला दिया। 18 दिसंबर को वेटनरी अस्पताल जहांगीराबाद में कंटेनर में भरे 265 क्विंटल (26.5 टन) मांस में से वेटनरी डॉक्टर की टीम ने अलग-अलग 5 डिब्बों में सैंपल लिए। बाकी मांस कंटेनर के ड्राइवर शोएब पिता कमालउद्दीन को ही सुपुर्दगी में दे दिया गया।

मथुरा की लैब में भेजे गए सैंपल

पुलिस ने जो सैंपल कंटेनर में मिले मांस के लिए थे, उन्हें पुलिस ने जांच के लिए फोरेंसिक लेबोरेटरी मथुरा को भेजे। संदिग्ध मांस के सैंपल की जांच रिपोर्ट भी मिल गई। जिसमें मांस में गोमांस (SAMPLE BELONG TO COW OR IT'S PROGENY) का होना सामने आया। गोमांस की पुष्टि होने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने अरेरा हिल्स थाने के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने जिंसी स्थित आधुनिक स्लॉटर हाउस का संचालन करने वाली लाइव स्टाक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड में पहुंचकर दस्तावेज जब्त किए थे। स्लॉटर हाउस का संचालक असलम चमड़ा कुरैशी का होना पाया गया है। इसके बाद निगम से स्लॉटर हाउस से जुड़ी सारी जानकारी पुलिस ने ली। ड्राइवर शोएब पिता कमालउद्दीन निवासी थाना खरखोदा मुस्कान पब्लिक स्कूल के पास इकबाल नगर हुमायूं नगर मेरठ (यूपी) से पूछताछ की गई। जांच के बाद पुलिस ने संचालक असलम चकड़ा, ड्राइवर शोएब व अन्य के विरुद्ध मप्र गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 5 और 9, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धार 61 (2) के तहत केस दर्ज किया।

महाकाल में 'शिव विवाह' से पहले 'हल्दी खेला' पर आपत्ति

महा शिवनवरात्रि पर महिलाएं नाच-गा रहीं; पुजारी बोले-शास्त्रों में उल्लेख नहीं, रोक लगे

उज्जैन। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में महिलाओं द्वारा एक-दूसरे को हल्दी लगाकर नाच-गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर के पुजारियों ने इसे सनातन परंपरा के विपरीत बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। महाशिवरात्रि से पहले मनाए जा रहे महा शिवनवरात्रि के दौरान महिलाएं नाच-गा रही हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान महाकाल को दूल्हा बनाने से पहले शिवनवरात्रि के नौ दिनों तक हर दिन विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस दौरान सुबह मंदिर परिसर में कोटेश्वर भगवान का पूजन-अर्चन होता है। पूजन के बाद रोजाना दर्शन के लिए आने वाली करीब 50 से 100 महिलाएं भगवान शिव के विवाह का उत्सव मनाती हैं। भजन मंडली के साथ नाच-गाना करते हुए एक-दूसरे को हल्दी लगाती हैं। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि शिव नवरात्रि में केवल पूजा, आराधना और संकल्प की परंपरा है। यह पंचमी से शुरू होता है। इसे भगवान के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजकल लोग इसे शिव विवाह के रूप में मानते हैं। इसे मजाक के रूप में हल्दी लगाने और खेलने के रूप में ले लिया गया। जबकि शिव पुराण और अन्य शास्त्रों में शिवरात्रि पर शिव विवाह और इस प्रकार मनाने का जिक्र

नहीं है। हल्दी खेलना सनातन परंपरा के विपरीत है। हल्दी लगाने की परंपरा भी घातक न हो जाए। इसलिए मंदिर समिति से इस पर समय रहते प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

मंदिर प्रशासन को भी मिली हल्दी खेलने की शिकायत

मंदिर प्रशासन को भी इस संबंध में शिकायतें मिली हैं कि मंदिर परिसर में परंपरा के विपरीत हल्दी खेलने का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद प्रशासक ने संकेत दिए हैं कि इस पर रोक लगाई जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही प्रशासक इस संबंध में आदेश जारी कर देंगे। दरअसल, मंदिर परिसर में कोटेश्वर भगवान को उबटन अर्पित करने की परंपरा है। नौ दिन तक भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान को दूल्हे के रूप में सजाकर सेहरा अर्पित किया जाता है। यही वजह है कि श्रद्धालु इसे शिव विवाह के रूप में मनाने लगे हैं। महाकाल मंदिर में नियमित दर्शन के लिए आने वाली महिलाओं ने करीब 11 साल पहले हल्दी खेलने की परंपरा की शुरूआत की थी। महिलाएं ढोल की थाप पर नाचती हैं। इस तरह वे एक-दूसरे को हल्दी लगाकर उत्सव मनाने लगीं।

मध्यप्रदेश पुलिस ने चोरी एवं रेलवे संपत्ति चुराने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस अपने ध्येय वाक्य 'देशभक्ति-जनसेवा' के अनुरूप प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं नागरिकों की आस्था व संपत्ति की सुरक्षा हेतु सतत् एवं ठोस कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों में चोरी की गंभीर घटनाओं का सफल खुलासा करते हुए पुलिस ने लगभग 37 लाख 40 हजार रूपए से अधिक मूल्य का चोरी की सामग्री जप्त की है।

पन्ना- रेलवे स्टेशन भवन से चोरी गई सामग्री बरामद- थाना देवेंद्रनगर क्षेत्र में नागौद-खजुराहो रेलवे प्रोजेक्ट के तहत ग्राम फुलवारी स्थित रेलवे स्टेशन भवन से केबल, वायर, पीवीसी पाइप एवं अन्य इलेक्ट्रिकल सामग्री की चोरी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 20 लाख रूपए की संपत्ति जप्त की है।

विदिशा- तीन चोरी के प्रकरणों का खुलासा- जिले के थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुखबिर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तीन अलग-अलग चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की बोलेरो पिकअप वाहन, मंदिर से चोरी किया गया मुकुट एवं छत्र तथा चोरी किया गया बिजली तार सहित लगभग 9 लाख 20 हजार रूपए की सामग्री जब्त की है।

शाजापुर-ग्राम जावदी स्थित हनुमान मंदिर चोरी का खुलासा- शाजापुर जिले के थाना मोहन बड़ोदिया क्षेत्रांतर्गत ग्राम जावदी स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने 600 से अधिक सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य एवं साइबर सेल की सहायता से सफलतापूर्वक खुलासा कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

भाजपा के नेता की गुंडागर्दी, समझौते के 20 दिन बाद 2 युवकों पर हमला

कार में भी तोड़फोड़ की, वर्चस्व के विवाद में झगड़े की शुरूआत

इंदौर। भाजपा से जुड़े नेताओं के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका ताजा मामला राऊ इलाके में देखने में आया। भाजयुमो के मंडल उपाध्यक्ष वेदांत तिवारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दो युवकों पर जानलेवा हमला किया। हमलावरों ने न सिर्फ युवकों को लाठियों से पीटा, बल्कि उनकी स्कॉर्पियो कार को भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।

गंभीर रूप से घायल प्रखर शर्मा और नयन बाफना को सिर में गहरी चोटें आई हैं। उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। 20 दिन पहले इसी मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया था। उसी समझौते ने आरोपियों के हौसले और बढ़ा दिए और उन्होंने दोबारा हमला कर दिया। घटना केट रोड पर रविवार तड़के 4.30 बजे की है। भाजपा नेता वेदांत तिवारी, समीर शर्मा और आदित्य ने प्रखर शर्मा और युवकों का केट रोड से पीछा किया और बीच रास्ते में रोककर हमला बोल दिया। दोनों पक्षों के बीच वर्चस्व की रंजिश चली आ रही है।

ये थी विवाद की पृष्ठभूमि- पुलिस ने बताया कि वेदांत तिवारी अपने कुछ मित्रों के साथ होटल से खाना खाकर लौट रहे था, तभी प्रखर से सामना हो गया। आमने-सामने होने पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। उधर, घटना के बाद पीड़ितों और उनके समर्थकों ने थाने पर हंगामा किया, तब जाकर पुलिस को दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा। घटना के बाद वेदांत ने वीडियो जारी कर मामले पर सफाई दी और कहा कि गुंडों ने उन पर हमला किया था।

जलीय पक्षी गणना : भोपाल के बिशनखेड़ी में 129 प्रजाति के पक्षी

सबसे ज्यादा पक्षी जबलपुर के मोहारी पॉन्ड में, भोज वेटलैंड में 2430 जलीय पक्षी मिले

भोपाल। भोपाल के जलाशय अब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि देशी-विदेशी परिंदों की पसंदीदा ठिकाना भी बनते जा रहे हैं। इसका प्रमाण 40वें एशियन वाटरबर्ड सेंसस का ताजा डेटा देता है। इस गणना के तहत पहली बार पूरे मध्य प्रदेश में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की एक साथ गणना की गई। इसमें प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व, 16 वन वृत्त और 63 वन मंडल शामिल किए गए। सामान्य वन मंडलों में गणना पूरी हो चुकी है। गणना में पक्षियों की सबसे अधिक प्रजातियां जबलपुर वन मंडल में दर्ज की गईं। वहीं रामसर साइट भोज वेटलैंड, बिशनखेड़ी (भोपाल) प्रजातियों के मामले में प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा रातापानी क्षेत्र के दाहोद, कलियासोत और हलाली डेम में भी विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पाए गए हैं। टाइगर रिजर्व और अभयारण्यों के जलाशयों में यह गणना प्रक्रिया 11 फरवरी तक जारी रहेगी। भोज वेटलैंड सिर्फ प्रजातियों की विविधता में ही नहीं, बल्कि जलीय पक्षियों की संख्या में भी आगे रहा। यहां 2430 जलीय पक्षी

दर्ज है। इससे यह प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। वहीं कलियासोत डेम चौथे और हलाली बांध पांचवें स्थान पर रहा। गणना के दौरान इंडियन स्पॉट-बिल्ड डक, यूरेशियन मूरहेन, सारस क्रेन, रेड-वॉटल्ड लैपविंग, व्हाइट-थ्रोटेड किंगफिशर, एलेक्जेंड्राइन पैराकीट, एशी प्रिनिया, ब्लैक ड्रोंगो, रेड-वेंटेड बुलबुल जैसी प्रजातियां दर्ज की गईं। गुलाबी मैना, साइबेरियन स्टोनचैट, यूरेशियन रेने, यूरेशियन केस्ट्रेल और कश्मीर से आने वाला टाइगा फ्लायकैचर भी दिखा। पूरी गणना ई-बर्ड ऐप के माध्यम से की गई, जिससे डेटा को डिजिटल रूप से दर्ज और विश्लेषित किया गया।

पक्षियों की प्रजातियों की स्थिति- जलाशय-प्रजातियां मोहारी पॉन्ड, जबलपुर- 139 भोज वेटलैंड बिशनखेड़ी- 129 दाहोद जलाशय- 119 कलियासोत भोपाल- 118 हलाली बांध- 116 रंगाई तालाब- 113 सिरपुर झील इंदौर- 103। यह पहला अवसर है, जब जंगलों और जल स्रोतों की सेहत का आकलन पक्षियों की मौजूदगी के आधार पर किया गया। सर्वे में जिन इलाकों में पक्षियों की प्रजातियां अधिक दर्ज हुईं, वहां वेटलैंड को सुरक्षित रखने की जरूरत स्पष्ट हुई। अध्ययन से यह भी सामने आया कि शहरी क्षेत्रों के जलाशयों में भी उल्लेखनीय जैव विविधता मौजूद है। इससे संकेत मिलता है कि सही संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन से शहरी जल स्रोत भी पर्यावरणीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।